राष्ट्रीय सेमिनार

मकतब–मदरसों में प्राथमिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण

30 अगस्त, 2008, स्थान-लखनऊ

रिपोर्ट

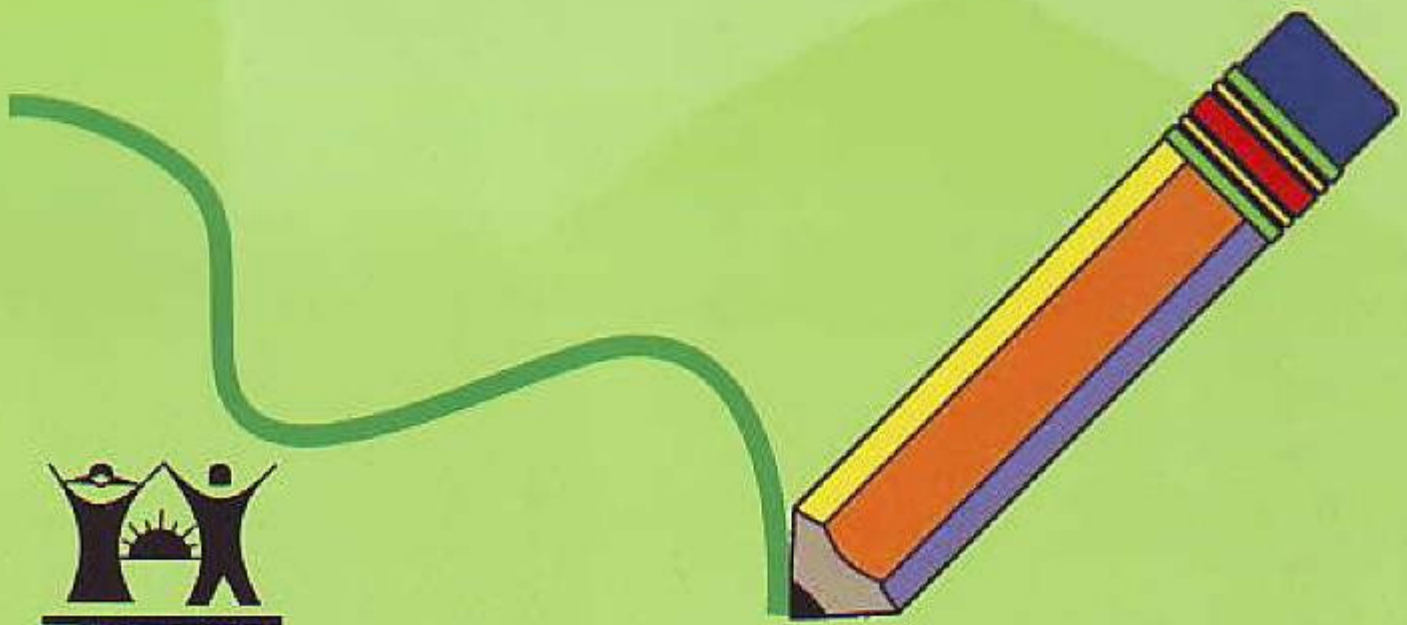

नालन्दा

''मकतब—मदरसों में प्राथमिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण''

(राज्य स्तरीय सेमिनार)

30 अगस्त 2008
स्थान : लखनऊ

रिपोर्ट

नालंदा

B-1/84, सेक्टर – B, अलीगंज, लखनऊ – 226 024
Tel. : 0522-2329751, 4028035
Email : nalanda_lko@rediffmail.com

राज्य स्तरीय सेमिनार रिपोर्ट

(30 अगस्त 2008)

स्थान : लखनऊ

मकतब–मदरसों में प्राथमिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण

मदरसों का गरीब अल्पसंख्यकों की शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान है, पर आज यह व्यवस्था ठीक से नहीं चल पा रही है। इसके कारण छात्रों, शिक्षकों और समाज, सभी को समस्या है। इसे सुधारने के लिए कई दृष्टिकोण सामने आते हैं जिनको समझने और समुचित रूप से लागू कराने के लिए प्राथमिक शिक्षा विशेषज्ञों की आवश्यकता है। हमें याद रखना होगा कि आजाद हिन्दुस्तान आज तेजी से आगे कदम बढ़ा रहा है। हमें इस प्रगति को सभी तक पहुंचाने के लिए साथ–साथ चलना है। आज दीनी तालीम के लिए भी संसाधनों की जरूरत है तथा अपने छात्रों और मुस्लिम समाज के सर्वांगीण विकास के लिए मदरसा तालीम को दुनियावी तालीम से भी पूरी तरह जोड़ना जरूरी है। इस्लामी समाज एक समय ज्ञान और प्रगति का पर्याय रहा है पर बाद में कुछ कारणों से वह इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाया। लगता है समय बीतने के साथ हमारी शिक्षा एकांगी होती गई जबकि इस्लाम में दीनो–दुनिया एकसाथ लेकर चलने की बात है। हजरत अली ने फरमाया है कि वह इल्म, इल्म नहीं जिससे फायदा न हो। इसलिये आज मदरसों में हमें अरबी–उर्दू के साथ–साथ हिन्दी व अंग्रेजी सिखाने पर बराबर का जोर देना होगा। जहां मदरसा कोर्सों को सरकार द्वारा मान्यता देने तथा उनके द्वारा दी जाने वाली डिग्रियों को मुख्यधारा शिक्षा के समान मानने की जरूरत है वहीं मदरसों को आधुनिक बनाने की भी जरूरत है। मदरसों को आधुनिक बना कर उनमें दुनियावी शिक्षा को समुचित रूप से डाला जा सकता है। हम प्राथमिक शिक्षा विशेषज्ञों, मदरसा शिक्षकों व छात्रों तथा समुदाय से समुचित संपर्क विकसित कर यह काम कर सकते हैं। उम्मीद करनी चाहिये कि ऐसे सेमिनार इस दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान करेंगे।

गिरि विकास अध्ययन संस्थान के प्रोफेसर एस.एस.ए.जाफरी ने इन शब्दों में नालन्दा, लखनऊ द्वारा आयोजित सेमिनार का समापन वक्तव्य दिया।

'मकतब–मदरसा में प्राथमिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण' पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन प्राथमिक शिक्षा सुदृढ़ीकरण में अग्रणी भूमिका निभाने वाली संस्था 'नालन्दा' द्वारा दिनांक 30 अगस्त, 2008 को सहभागी शिक्षण केन्द्र, लखनऊ में किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रीय स्तर के मानवशास्त्री व लखनऊ विश्वविद्यालय में मानव शास्त्र विभागाध्यक्ष प्रो. नदीम हसनैन ने किया। प्रो. हसनैन फुलब्राइट स्कालरशिप के अंतर्गत एक अमेरिकी विश्वविद्यालय में दो साल शिक्षण कार्य के बाद हाल ही में भारत वापस आये हैं। शिक्षण के अतिरिक्त वे सांप्रदायिकता–विरोधी आंदोलन व मुस्लिम समाज की बेहतरी के अनेक कामों में लगे रहे हैं और इस लिहाज से एक जानी–मानी सख्शियत हैं। सम्मेलन में दिल्ली विश्वविद्यालय के वरिष्ठ व्याख्याता डा. नईमुल हसन ने भाग लिया जिनका मदरसा शिक्षा को आधुनिक बनाने तथा मदरसा शिक्षकों के प्रशिक्षण में अग्रणी योगदान है। सेमिनार के एक और संदर्भ व्यक्ति जामिया मिलिया इस्लामिया के डा. मुज्जमिल हुसैन कासमी का भी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम है। यहीं के डा. जसीम अहमद शिक्षक प्रशिक्षण व अनौपचारिक शिक्षा के विशेषज्ञ हैं। स्थानीय गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ के प्रो.एस.एस.ए.जाफरी ने मुस्लिम समाज की स्थिति तथा उनके विकास पर अनेक अध्ययन किये हैं। लखनऊ के ही हिन्दी–उर्दू साहित्यकार व सामाजिक कार्यकर्ता शकील सिद्दीकी ने विभिन्न मदरसों में पढ़ाई जाने वाली किताबों का विशेष अध्ययन किया है जिसे दिल्ली से प्रकाशित एक लोकप्रिय पत्रिका ने दो अंकों में छापा है। एक प्रखर सामाजिक–राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर भी उनकी पहचान है। इन सभी विशिष्ट अतिथियों ने सेमिनार में अपने आलेख पढ़े। सम्मेलन में मदरसों के शिक्षकों–शिक्षिकाओं तथा प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत कई स्वयंसेवी संस्थाओं के

लगभग 50 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रत्येक वक्ता के बाद तथा खुले सत्र में जीवन्त विचार–विमर्श ने सेमिनार को लाभदायक बनाने में अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान किया। सेमिनार की शुरुआत में नालन्दा, लखनऊ के निदेशक श्री प्रभात झा ने प्रतिनिधियों व विशिष्ट अतिथियों का स्वागत किया तथा नालन्दा में मदरसा शिक्षा के संयोजक श्री मुहम्मद आसिम सिद्दीकी ने इस दिशा में संस्था द्वारा उठाये कदमों की जानकारी दी।

नालन्दा के प्रयास

सेमिनार के सहभागियों व विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करते हुए नालन्दा, लखनऊ के निदेशक श्री प्रभात झा ने बताया कि नालन्दा पिछले 10 वर्षों से प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है। संस्था संदर्भ केन्द्र के तौर पर काम करते हुए शिक्षकों की क्षमतायें बढ़ाने के लिए निरन्तर तकनीकी व अकादमिक सहयोग किया जा रहा है। नालन्दा के षैक्षिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। नालन्दा लड़कियों तथा आदिवासियों की शिक्षा के क्षेत्र में भी सक्रिय है। संस्था ने पिछले 5 वर्षों से मकतब–मदरसा शिक्षा में काम करना शुरू किया है। मदरसा कार्यक्रम की शुरुआत अचानक ही बाराबंकी में डीपीईपी कार्यक्रम के बाद हुई। इस कार्यक्रम में मदरसों के अनेक शिक्षक भाग ले रहे थे जिनको प्रशिक्षण के अवसर बहुत कम मिले थे। संस्था ने इस कार्यक्रम के बाद मदरसा शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा मदरसों को मजबूत करने पर ध्यान देना शुरू किया। हमें साफ नजर आया कि मदरसों में दीनियाती शिक्षा के तरीके अन्य विषयों की शिक्षा में भी शामिल थे जबकि आधुनिक शिक्षण पद्धतियों ने बच्चों तथा शिक्षकों को केन्द्र में रखने के अनेकानेक प्रयोग किये थे। मदरसों में इस स्थिति को बदलने की जरूरत है। हमारा विश्वास है कि आधुनिक बाल केन्द्रित आनन्ददायक शिक्षा सिद्धान्तों को लागू कर मदरसों के छात्र सामाजिक विकास में और बेहतर योगदान कर सकते हैं। इस संबंध में हमने लगातार मुदर्रिसों से संवाद स्थापित करने के प्रयास किये हैं। संस्था वर्तमान समय में 200 मदरसों में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है। इनमें से 40 मदरसे झारखंड में हैं।

प्रो. नदीम हसनैन के उद्घाटन भाषण के बाद नालन्दा के मकतब–मदरसा शिक्षा कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताते हुए संस्था में इस मामले पर कोआर्डीनेटर श्री आसिम सिद्दीकी ने कहा कि हमारा उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के प्रति मदरसों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना है ताकि वे दीनी तालीम के साथ प्राथमिक षिक्षा पर भी जोर दे सकें। खुशी की बात है कि अधिकांश मदरसे दीनी तालीम के साथ प्राथमिक षिक्षा देना चाहते हैं। वर्तमान समय में 98 प्रतिशत मुदर्रिसों को किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है। हम मुदर्रिसों व संदर्भ व्यक्तियों के बीच सेतु बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि मुदर्रिसों का क्षमतावर्धन किया जा सके। नालन्दा इसके लिए संदर्भ पैकेज बनाने का प्रयास कर रहा है। संस्था का प्रयास है कि मदरसों में बाल–केन्द्रित शिक्षा अपनाई जाये जिससे मुदर्रिस बच्चों की खूबियां निखार कर उनको मुख्यधारा शिक्षा में समाहित करने योग्य बना सकें।

श्री सिद्दीकी के अनुसार नालन्दा, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, सीतापुर व भदोही के 13 ब्लाकों में काम कर रहा है। यहां 45 क्लस्टरों का गठन कर 1045 मदरसा शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। संस्था ने शिक्षक प्रशिक्षण के लिए 'परवाज' व 'पारस' माड्यूलों का विकास किया है। हमने अब तक 3, 4 और 5 दिन के शिक्षक प्रशिक्षण सत्र चलाये हैं। संस्था का प्रयास है कि मुदर्रिसों को साल भर में कम से कम 10 दिन का प्रशिक्षण अवश्य दिया जाये। संस्था ने बच्चों के लिए उर्दू में 'अपनी किताब' व 20 उर्दू कहानियों का संग्रह छापा है। हम मुदर्रिसों तथा मदरसा छात्रों के लिए अन्य पुस्तकों का प्रकाशन भी जल्द ही करने वाले हैं। नालन्दा पाठ्य पुस्तकों के अलावा छात्रों को पाठ्येत्तर सहायक पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने के प्रयास भी कर रही हैं। संस्था मदरसों के कम से कम 30000 बच्चों तक पहुंच बनाने तथा सभी मदरसों के लिए समान पाठ्यक्रम विकसित करने के प्रयास कर रही है। हालांकि अधिकांश मुदर्रिस बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए बेहतर दुनियावी तालीम भी चाहते हैं पर

कहीं–कहीं संकुचित विचार बाधा के रूप में हमारे सामने आये हैं। हम मुदर्रिसों से और गहन विचार–विमर्श करने तथा मदरसा शिक्षा के बारे में उनकी राय जानने के प्रयास बढ़ाने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान सेमिनार इन प्रयासों की एक कड़ी है।

उद्घाटन भाषण

प्रोफेसर नदीम हसनैन ने प्लेटो की मशहूर कहावत–'खुशियों का आधार ज्ञान' का जिक्र करते हुए याद दिलाया कि हमेशा से इस्लाम और ज्ञान के बीच अटूट संबंध रहा है। उन्होंने वह घटना भी याद दिलाई कि एक बार पैगम्बर हजरत मुहम्मद स.अ ने युद्ध में कैद कुछ लोगों को मुसलमानों को पढ़ना–लिखना सिखाने की शर्त पर रिहा करने की पेशकश भी की थी। उनकी यह बात आज भी लोगों की जुबान पर है कि अगर शिक्षा के लिए चीन भी जाना पड़े तो मंजूर है। नदीम साहब ने जोर दिया कि शिक्षा समग्र व संपूर्ण होनी चाहिये और मदरसों की तालीम भी इससे अलग नहीं है। उन्होंने जिक्र किया कि अल्लाहताला ने फरमाया है कि हमने तुम्हारे लिये जमीन में खजाने दिये हैं। अब बिना भूगर्भ विज्ञान जैसी दुनियावी तालीम के हम इन खजानों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआत में दुनियावी या सेक्युलर शिक्षा इस्लामी ज्ञान का महत्वपूर्ण हिस्सा रही पर कालान्तर में यह धीरे–धीरे हाशिये पर खिसकने लगी। इसके कारण इस्लामी समाजों में ज्ञान के उत्पादन और उपभोग पर नकारात्मक असर पड़ा है। यह हालत पैदा करने में औपनिवेशिक ताकतों की भी बड़ी भूमिका रही है। औद्योगिक क्रान्ति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में पिछड़ने के कारण इस्लामी दुनिया लंबे समय तक गुलामी की गिरफ्त में जकड़ी रही। इस्लामी समाजों में शुरुआत में इज्तिहाद (तार्किक विश्लेषण) का दौर चला जो बाद में समाप्त हो गया। उस समय इस्लामी समाज ज्ञान के हर क्षेत्र में सबसे आगे रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि हजरत मुहम्मद की बीबी अपने समय की एक प्रमुख व्यापारी या इंटरप्रोन्योर थीं पर अफगानिस्तान की तालिबानी हुकूमत में औरतों को शिक्षा से ही महरूम कर दिया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज गलती से पश्चिमीकरण को आधुनिकता का पर्याय मान लिया गया है जबकि ऐसा नहीं है। अनेक पूर्वी समाज जैसे चीन और जापान आदि ने अपनी सभ्यता–संस्कृति बनाये रखते हुए आधुनिक प्रगति में तेजी से कदम बढ़ाये हैं। हमने लंबे समय तक समाज विज्ञान को नजरंदाज किया है पर आज इस्लामी समाज को शरीयत से वाकिफ समाज विज्ञानी और समाज विज्ञान से वाकिफ उलेमाओं की जरूरत है। प्रो. हसनैन ने दक्षिण भारत के आधुनिक और सारी सहूलियतों वाले मदरसों का जिक्र करते हुये सवाल उठाया कि उत्तर भारत के मदरसे भी ऐसे क्यों नहीं हो सकते हैं? मुसलमानों को सेक्युलर एनजीओ के साथ काम करने की हिचक छोड़ने की सलाह और सेमिनार की कामयाबी की कामना करते हुए उन्होंने अपनी बात समाप्त की।

शिक्षा प्रसार और मदरसे

दिल्ली विश्वविद्यालय के अरबी विभाग में वरिष्ठ व्याख्याता डा. नईमुल हसन ने 'भारत में शिक्षा प्रसार में मदरसों की भूमिका' पर अपना शोधपत्र प्रस्तुत किया। डा. हसन ने बड़ी साफगोई से कहा कि आज बाजार की मांग ही शिक्षा का मूल्यांकन कर रही है और ज्यादातर लोग इसके अनुसार ही केवल नौकरी दिलाने वाले कोर्सों की ओर रुख कर रहे हैं। इस लिहाज से मदरसा शिक्षा अपना महत्व खोती जा रही है। खूब कमाने वाले अमीर लोग अपने बच्चों को सजे–धजे स्कूल कालेजों में भेजते हैं यहां तक कि अमीर मुस्लिम भी अपने बच्चों को आधारभूत इस्लामी ज्ञान दिलाने तथा कुरान, हदीस और शरीया समझाने की खास फिक्र नहीं करते हैं। वास्तव में गरीब मुस्लिम तबके के थोड़े से लोग अपनी आर्थिक समस्याओं के कारण बच्चों को मदरसे में धार्मिक शिक्षा के लिए भेजते हैं। तरक्की की दौड़ में दूसरों की तरह आगे न निकल पाने तथा समाज की मांगे पूरी न कर पाने के कारण अनेक मुसलमान भी मदरसा स्नातकों को सम्मान की नजर से नहीं देखते हैं।

आज हालात और बिगड़ गये हैं। मदरसों का तिरस्कार किया जा रहा है तथा मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इनको आतंकवाद के अड्डे बता कर निशाने पर ले रहा है। पर, सच्चाई यह है कि मदरसों ने ऐतिहासिक रूप से शिक्षा फैलाने और विज्ञान के प्रसार में भारी योगदान दिया है। अरब दुनिया में इस्लाम के पैदा होने से लेकर चार खलीफाओं के स्वर्ण युग तथा स्पेन, अफ्रीका व एशिया तक फैले उमय्याद और अब्बासी शासकों के समय में केवल मकतब व मदरसे ही ज्ञान का केन्द्र होते थे। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम अबू हनीफा, गजाली, इब्न रशीद, इब्न–सिना, आदि इन्हीं मस्जिदों और मदरसों से निकले थे। 1065–67 में निजाम–उल–मुल्क द्वारा स्थापित निजामिया को इस्लामी उच्च शिक्षा का आधारस्तम्भ कहा जाना चाहिये। भारत में मदरसों का इतिहास मुसलमानों के आने के बाद शुरू होता है। मध्यकालीन भारत में सरकार इनको हर तरह की मदद देती थी जिसके चलते पूरे भारत में अनेकानेक मदरसे स्थापित हुए। बहुत बाद तक मदरसे बहुसंख्यक गैर–मुस्लिमों को भी आकर्षित करते रहे हैं। भारत के महान नेताओं जैसे राजा राममोहन राय, डा. राजेन्द्र प्रसाद, डा. सच्चिदानन्द सिन्हा, आदि अनेकानेक लोगों ने प्राथमिक शिक्षा मदरसों में पाई।

आज भी हिन्दुस्तान के हर इलाके में मकतब–मदरसे फैले हुए हैं तथा सरकार मदरसा शिक्षा व्यवस्था में सुधार के प्रयास कर रही है। न केवल सरकार बल्कि मुस्लिम समाज भी इस मुद्दे पर लगातार सोच–विचार और महत्वपूर्ण काम कर रहा है। मदरसों में सुधार के कारण ही आज मदरसों के स्नातक सरकारी विश्वविद्यालयों, कालेजों और कार्यालयों में दिखाई देते हैं तथा इनकी संख्या भी बढ़ रही है। लड़कियों के लिए भी काफी मदरसे खुल गये हैं जो उनको 'आलिमा' के तौर पर प्रशिक्षित करते हैं। मुस्लिम समाज में यह एक नया कदम है। मदरसा स्नातकों को दूसरे विश्वविद्यालयों के भाई–बहनों के साथ कंधे से कंधा मिला कर खड़ा होने के लिए तैयार करने हेतु हमें अपने वर्तमान पाठ्यक्रमों में परिवर्तन की आवश्यकता है ताकि उसमें दीनियाती शिक्षा के साथ विज्ञान शिक्षा को भी शामिल किया जा सके। केरल के मदरसों में स्कूली तालीम के लिए अलग से समय दिया जाता है। हमें मदरसों में शिक्षण की नई विधियां लागू करने व शिक्षकों को सेवा से पहले तथा सेवा के दौरान प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। हमें राज्य और केन्द्रीय सरकार से कम से कम हायर सेकेन्ड्री स्तर तक सभी मदरसों को बिना शर्त मान्यता देने की प्रार्थना करनी चाहिये ताकि इन मदरसों के स्नातक खुद को तथा पूरे मुस्लिम समाज को देश की मुख्यधारा में ला सकें।

डा.नईमुल हसन के शोधपत्र के बाद प्रतिभागियों ने अनेक सवाल पूछे। एक मुदर्रिस ने मदरसों में पैसों के संकट की ओर ध्यान खींचा। डा. हसन ने पैसे के संकट की बात स्वीकार करते हुए उपलब्ध संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल से फायदा उठाने की बात की। उन्होंने कहा कि बच्चों को रटाने के बजाय आधुनिक शिक्षा विधियों के अनुसार सीखने–सिखाने के प्रयास करने चाहिये। उन्होंने मुदर्रिसों से दुनियावी शिक्षा पर भी समुचित जोर देने की बात की।

मुदर्रिसों का प्रशिक्षण

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली में व्याख्याता डा. मुज्जिमल हुसैन कासमी ने 'प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मदरसा शिक्षकों का आवश्यकता आधारित सेवाकालीन प्रशिक्षण' पर अपना शोधपत्र रखा। उन्होंने कहा कि मदरसा शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए जरूरत के लिहाज से शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मदरसा शिक्षकों का प्रशिक्षण होना चाहिये। इसका उद्देश्य; कुशल, सक्षम, प्रतिबद्ध तथा परिणाम देने वाले शिक्षक तैयार करना; कार्यस्थल पर कौशल बढ़ाने की योजनायें प्रोत्साहित करना, प्रशिक्षण शुरू करने से पहले प्रशिक्षकों व शिक्षकों की जरूरतों का अध्ययन करना तथा प्रशिक्षण की विभिन्न जरूरतें समझना है। उन्होंने बताया कि सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने से पहले जामिया मिलिया ने दिल्ली के 380 मदरसों तथा उनके शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की जरूरतों का सर्वेक्षण कराया। सर्वेक्षण के लिए तैयार की गई प्रश्नावलियों का लगभग 1500 शिक्षकों ने जवाब दिया। इनमें शिक्षकों से उनके पढ़ाने वाले विषय, विषय के कठिन अध्यायों, सहायक शिक्षण सामग्री के

उपयोग, उनकी दिलचस्पी के क्षेत्र तथा अधिक जानकारी की इच्छा वाले क्षेत्रों के बारे में पूछा गया था। उनसे यह भी पूछा गया था कि क्या वे तकनीक का प्रयोग कर अपना कौशल बढ़ाना चाहते हैं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम से उनको क्या उम्मीदें थीं। सर्वेक्षण के बाद जरूरत के अनेक क्षेत्रों का चयन किया गया। इनमें इस्लामी शिक्षा सहित शिक्षा के अन्य दर्शन, बाल मनोविज्ञान, शिक्षा और समाज, पाठ्यक्रम विकास, पढ़ाने के विभिन्न तरीके, विभिन्न विषयों की पाठ योजनायें बनाना, मूल्यांकन, कम्प्यूटर प्रशिक्षण, आदि शामिल थे।

डा.कासमी ने अपने आलेख में प्रशिक्षकों व प्रशिक्षुओं की जिम्मेदारियों का भी उल्लेख किया। जहां प्रशिक्षकों के लिए समुचित निर्देशन व सहायता देने, प्रशिक्षुओं को विकसित करने के लिए अर्थवान प्रशिक्षण देने तथा उनकी उपलब्धि के मूल्यांकन में समुचित सहभागिता करने की जिम्मेदारियां होती हैं वहीं प्रशिक्षुओं को भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रशिक्षक से सहयोग करने, कार्य अनुभव द्वारा सीखने की इच्छा रखने तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम का पूरा लाभ उठाने की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने सीखने की समुचित परिस्थितियां तैयार करने पर जोर दिया ताकि स्वयं छात्र अपने शिक्षण स्तर का मूल्यांकन कर सके। डा. कासमी ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा–2005 के अंतर्गत तैयार पुस्तकों की प्रशंसा करते हुए बताया कि इसमें हर पाठ के बाद छात्र द्वारा स्वयं किये अभ्यासों को नये तरीके से शामिल किया गया है जिनसे छात्र स्वयं अपने अध्ययन स्तर का मूल्यांकन कर सकता है। उन्होंने मुदर्रिसों से बच्चों को उनके परिवेश से जोड़ कर समझाने पर जोर दिया। स्थानीय मौसम, त्यौहार, सरकार के प्रकार आदि का इस तरह प्रयोग किया जा सकता है। उन्होंने संदर्भ केन्द्र को शिक्षकों की कक्षाओं में जाकर कार्यक्रम क्रियान्वयन पर नजर रखने तथा प्रशिक्षण बेहतर बनाने के लिए फीडबैक का रिकार्ड रखने की सलाह भी दी।

आलेख प्रस्तुत करने के बाद डा. मुज्जिमल ने सहभागियों के सवालों के जवाब दिये। एक महिला सहभागी ने लड़कियों की शिक्षा व व्यक्तित्व विकास तथा मदरसा छात्रों के समाज में ठीक से व्यवस्थित न होने पाने की समस्या उठाई। डा. कासमी ने स्वीकार किया कि अधिकांश मदरसों में लड़के ही हैं पर अब लड़कियों के लिए मदरसे खोलने की रफ्तार बढ़ी है। दिल्ली में महिलाओं के लिए चार मदरसे हाल ही में खुले हैं। मदरसा छात्रों को बहस–मुहाबसे, नाटकों में भाग लेने, आदि के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ताकि उनका व्यक्तित्व विकसित हो सके और बाद में समाज में उनको कोई दिक्कत न हो। शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता पर डा. कासमी का कहना था कि बच्चे आमतौर से खेल–कूद जैसी गतिविधियों में अपने आप लगे रहते हैं। उन्होंने छात्रों की स्वास्थ्य जांच कर उनके स्वास्थ्य कार्ड बनाने तथा स्वास्थ्य व बीमारियों की पहचान के बारे में आधारभूत जानकारी देने की आवश्यकता बताई। मदरसों के शिक्षकों व छात्रों की आर्थिक आवश्यकताओं पर सवाल के जवाब में उन्होंने सीमित स्रोतों की बात स्वीकार करते हुए बताया कि केन्द्रीय सरकार ने मदरसा आधुनिकीकरण के लिए आर्थिक मदद की व्यवस्था की है पर इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों व जिला साक्षरता समिति (डीपीईपी) पर डाली है। अन्य विद्यालयों की तरह सारे मदरसों को मिडडे मील देने की व्यवस्था है। कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए भी सरकार मदद देती है जिसके लिए राज्य संसाधन केन्द्र से संपर्क करना चाहिये। शिक्षक प्रशिक्षण के लिए भी मौलाना आजाद फाउंडेशन से मदद मिल सकती है। मदरसों के लिए संसाधन व सुविधायें जुटाने के लिए सेमिनार में उपस्थित मुदर्रिसों, एनजीओ प्रतिनिधियों व विशिष्ट अतिथियों ने परस्पर सहयोग करने का वादा किया।

आधुनिक युग और मदरसा शिक्षा

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के शिक्षा विभाग में व्याख्याता डा. जसीम अहमद ने 'आधुनिक युग में मदरसा शिक्षा' पर अपना आलेख पढ़ा। उनका मानना था कि वैश्वीकरण और निजीकरण ने मदरसा शिक्षा सहित जीवन के सभी पक्षों को प्रभावित किया है। समाज में बढ़ती गतिशीलता के साथ मदरसा शिक्षा और उसके पाठ्यक्रम को भी गतिशील बनाना समय की आवश्यकता है। मदरसे के पढ़े

बच्चों में आज कमतरी का अहसास आमतौर से पाया जाता है। उनमें आत्मविश्वास पैदा करने की जरूरत है। मदरसों मे पढ़ने वाले बच्चों में दूसरे बच्चों जैसी सलाहियतें होती हैं। अगर उनको दूसरे बच्चों जैसी सुविधायें, बेहतर इमारत और बेहतर तालीम मिले तो जिन्दगी के सभी क्षेत्रों में वे दूसरे बच्चों का मुकाबला कर सकते हैं। हमें ऐसे प्रयास करने हैं कि मदरसे से निकलने के बाद छात्रों को इस्लाम का गहरा ज्ञान, समझदारी और उसे व्यवहार में उतारने की क्षमता के साथ ही उनमें समाज की चुनौतियों का मुकाबला करने तथा मदरसों के बाहर पढ़े छात्रों के साथ प्रतियोगिता के माहौल का मुकाबला करने की क्षमता भी विकसित हो। मदरसा शिक्षा की प्रमुख भूमिकाओं में धार्मिक व सांस्कृतिक भूमिका, विमुक्तिकारी भूमिका, बच्चों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना सिखाना तथा देश व समाज को जोड़ने की सलाहियत पैदा करना शामिल है।

डा. अहमद ने बताया कि मदरसा पाठ्यक्रम को अपने लक्ष्यों, विषय के संगठन, शिक्षा प्रक्रिया तथा छात्रों के मूल्यांकन के बारे में स्पष्ट होना चाहिये। बच्चों में रचनात्मक और स्वतंत्र चिन्तन क्षमताओं का विकास भी आधुनिक पाठ्यक्रमों का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पहले स्कूली शिक्षा में विज्ञान और गणित अनिवार्य विषय नहीं होते थे पर आज सभी स्तरों पर इनको अनिवार्य माना जाता है। भारतीय शिक्षा आयोग रिपोर्ट (1964–66) के अनुसार सेकेन्ड्री स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा पर काफी जोर दिया जाता है। मदरसों में समुदाय के कारीगरों को नियमित अंतराल पर थोड़े–थोड़े समय के लिए बुला कर बच्चों को अनेक व्यवसायों की शिक्षा दी जा सकती है। समुचित रूप से प्रेरित किये जाने पर कारीगर न केवल इसमें अपना योगदान देंगे बल्कि कौम की खिदमत समझ कर इसके लिये शायद कोई मेहनताना भी न मांगें। उन्होंने मुदर्रिसों से बच्चों से संवाद विकसित कर आधुनिक पद्धति से पढ़ाने–सिखाने पर जोर देने की बात की। ज्यादातर मदरसों में बच्चे केवल मुदर्रिसों की बातें सुनते और रटते हैं जिसमें केवल उनकी स्रवणेन्द्रियां यानी कान ही सक्रिय होते हैं। इसे बदलने की जरूरत है ताकि बच्चों की सभी ज्ञानेन्द्रियां अधिकाधिक सक्रिय हो सकें। बच्चों को प्रयोगात्मक शिक्षा देने की जरूरत है। उन्होंने विज्ञान को समाज से जोड़कर पढ़ाने का आग्रह किया और इसके लिए बड़े मनोरंजक तरीके से केमिकल बान्डिंग का उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह अनेकानेक अणु व परमाणु आपस में मिल कर नई चीजें बनाते हैं पर समाज के लोग तकलीफों में एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं। परमाणु अपने अतिरिक्त एलेक्ट्रान का दूसरे परमाणु से साझा कर नये यौगिक बना देते हैं, पर हमारे समाज में अमीर आदमी गरीबों की मदद नहीं करते हैं। उन्होंने मदरसा शिक्षकों को सेवा के दौरान लगातार प्रशिक्षण देने, छात्रों के निरन्तर मूल्यांकन तथा मदरसों को क्षेत्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर एक दूसरे से संबंध विकसित करने की बात कही। उन्होंने मदरसा शिक्षा बोर्ड पर मदरसों के बीच संपर्क विकसित करने तथा उनकी आर्थिक सहायता की जिम्मेदारी डाली।

डा. जसीम अहमद ने एक ग्राफिक्स के माध्यम से मदरसा शिक्षा पाठ्यक्रम का एक माडल प्रस्तुत किया तथा उसकी विस्तृत व्याख्या की। उनका मानना है कि समता, समानता और न्याय पर आधारित नई सामाजिक व्यवस्था विकसित करना हम सभी की जिम्मेदारी है। इसी तरह अपनी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा, राष्ट्रीय पहचान व एकता को मजबूत करना तथा क्षेत्रीयतावाद, जातिवाद व भाषावाद जैसी विघटनकारी ताकतों को परास्त करना भी हम सब का कर्तव्य है। इसके लिए चरित्र निर्माण, संवैधानिक दायित्वों के प्रति सम्मान, वैश्विक नजरिये का विकास, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा छोटे परिवार के आदर्श को भी समाहित करने की आवश्यकता है। देश के अन्य स्कूलों की तरह मदरसों को भी अपनी शिक्षा के माध्यम से इन बातों को छात्रों के व्यक्तित्व में शामिल करने की आवश्यकता है। इस्लामी शिक्षा को केन्द्र मान कर मदरसों को ऐसे स्नातक पैदा करने चाहिये जिनको न केवल इस्लाम का गहरा ज्ञान व समझदारी हो बल्कि इसे वे अपने व्यवहार में उतार कर दूसरों को इस्लाम की ओर आकर्षित भी कर सकें। इसके साथ ही सभी जरूरतमंद छात्रों को दो साल की गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक शिक्षा भी देनी होगी ताकि वे हायर सेकेन्ड्री/मौलवी कोर्स करते ही जल्दी से जल्दी आत्मनिर्भर हो सकें। हालांकि व्यावसायिक शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य होनी चाहिये, पर इसकी सबसे ज्यादा जरूरत निम्न, निम्न–मध्यम व मध्यम वर्ग के छात्रों को है। शिक्षक और शिक्षा

प्रशासक; शिक्षा प्रक्रिया, उसकी गुणवत्ता तथा परिणामों के लिए दिल और दिमाग की तरह हैं। उनके सक्षम, ईमानदार तथा प्रतिबद्ध हुए बिना कोई काम आगे बढ़ने वाला नहीं है। नई व आधुनिक जानकारियों तथा अपने विषय में नई–नई तरक्कियों से परिचित कराने के लिए सेवा के दौरान मुदर्रिसों व शिक्षा प्रशासकों का नियमित अंतराल पर प्रशिक्षण आवश्यक है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा–2005 का जिक्र करते हुए डा. जसीम अहमद ने बताया कि इसमें शिक्षकों की नई भूमिका की कल्पना की गई है। अब वे केवल ज्ञान को संप्रेषित करने वाले भर नहीं हैं। मदरसों को भी यह दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। इस नई भूमिका में शिक्षक, ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में छात्रों को अभिव्यक्ति, विश्लेषण व व्याख्या करने में सहायता करने वाले हैं। वास्तव में यह शिक्षा के रचनावादी सिद्धान्त के आधार पर है जहां सीखने वाला यानी छात्र, ज्ञान की रचना करता है तथा शिक्षक इसमें मदद करता है। इस नई शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक–छात्र के बीच स्वस्थ विचार–विमर्श, समुचित शैक्षणिक सामग्री एकत्र करना, व्यक्तिगत एवं सामूहिक चर्चा, प्रदर्शन एवं प्रयोग, परियोजना कार्य, खेल गतिविधि/शैक्षणिक खेल, शैक्षणिक भ्रमण, नाटक, खोज के माध्यम से सीखना, आदि प्रमुख तत्व हैं। यदि ईमानदारी से इस दृष्टिकोण पर अमल किया जाये तो यह मदरसा शिक्षा तथा बच्चों के दिमाग को बदल सकता है। छात्रों के मूल्यांकन की पुरानी प्रणाली पर सवाल उठाते हुए डा. अहमद ने 'निरन्तर एवं समग्र मूल्यांकन' की आन्तरिक प्रणाली की अवधारणा पर जोर दिया। इस प्रणाली से छात्रों के व्यक्तित्व का समग्र विकास किया जा सकता है। अपने आलेख के अन्त में डा. जसीम अहमद ने पूर्व राष्ट्रपति डा. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की वर्ष 2020 तक भारत को ज्ञान की महाशक्ति बनाने की बात याद दिलाते हुए जोर दिया कि बिना मदरसा और स्कूली पाठ्यक्रम में परिवर्तन किये ऐसा होना संभव नहीं है। इसके लिये सक्षम एवं सर्वोत्तम शिक्षक, शिक्षा व्यवस्था में सभी स्तरों पर ईमानदारी होनी चाहिये। शिक्षकों का समाज में सम्मानपूर्ण स्थान होना भी बहुत जरूरी है क्योंकि वे ही समुदाय, समाज और राष्ट्र के सच्चे निर्माता हैं।

मदरसा आधुनिकीकरण और भारतीय नजरिया

गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ के प्रोफेसर एस.एस.ए.जाफरी ने 'मकतब और मदरसा आधुनिकीकरणः भारतीय दृष्टिकोण' पर अपना आलेख प्रस्तुत किया। आलेख के पहले उन्होंने देश–प्रदेश में मुसलमानों की दयनीय दशा पर प्रकाश डालते हुए बताया कि आज देश में 20 करोड़ मुसलमान हैं। प्रदेश के 21 जिलों में मुसलमानों की जनसंख्या औसत से ज्यादा है, पर उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। जहां अन्य समुदायों की औसत आमदनी 26000 रुपये है वहीं मुसलमानों की औसत आमदनी केवल 4000 रुपये है। मुसलमानों का 25 प्रतिशत सीमान्त किसान है जबकि 40 प्रतिशत घरेलू उद्योगों पर निर्भर हैं। मुसलमान कारीगरों की औसत आमदनी 20 से 40 रुपये रोजाना है। मुसलमानों के 35 प्रतिशत बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं।

अपने आलेख में प्रो. जाफरी ने बताया कि अंग्रेजों के आने और मैकाले की शिक्षा पद्धति लागू होने से पहले पूरे देश में शिक्षा का माध्यम फारसी और उर्दू था। देश के अधिकांश भाग में यही सरकारी भाषायें भी थीं। अंग्रेजों के आने के बाद चूंकि आम धारणा यह बनी कि अंग्रेजी पढ़ा कर मिशनरी लोगों का धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं इसलिये मदरसे अंग्रेजी शिक्षा से अलग रहे। यहां तक कि मुसलमानों की तरक्की के लिए अंग्रेजी को जरूरी मानने तथा उसका प्रसार करने वाले सर सैय्यद अहमद खान को अंग्रेज एजेंट बता दिया गया। 1920 में देवबंद से अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए 'रेशमी रुमाल' जैसी तहरीक शुरू हुई जिसका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण स्थान है। आजादी के बाद भी मदरसों में आम समझ यही रही कि मुसलमानों के लिए आधुनिक शिक्षा धार्मिक व नैतिक रूप से हानिकारक है। असलियत यह है कि औद्योगिक क्रान्ति के बाद पूरे वैज्ञानिक ज्ञान पर पश्चिम का कब्जा है जो हमें अंग्रेजी और पश्चिमी शिक्षा प्रणाली द्वारा ही मिल सकता है। समुदाय द्वारा स्वेच्छा तथा बड़े भावनात्मक रूप से चलाये जाने वाले मकतब व मदरसे आज मुस्लिम

समाज में शिक्षा की रीढ़ की तरह हैं। वर्तमान मदरसा पाठ्यक्रमों में सभी विषय पूरी गम्भीरता तथा अनुशासन के साथ पढ़ाये जाते हैं, पर शिक्षण की भाषा अंग्रेजी या हिन्दी न होने के कारण इनके छात्रों को आगे चल कर बहुत समस्यायें होती हैं। उनकी डिग्रियों को मुख्यधारा शिक्षा की तरह मान्यता नहीं मिलती है। आज मकतब–मदरसों की परंपरागत शिक्षा प्रणाली को आधुनिक शिक्षा प्रणाली में बदलने की जरूरत है ताकि अपनी परंपरागत भूमिका अदा करने के साथ वे मुख्यधारा शिक्षा में भी अपनी भूमिका अदा कर सकें।

प्रो. जाफरी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 30,000 मकतब हैं जहां पवित्र कुरान, उर्दू, प्राथमिक समाज विज्ञान एवं गणित पढ़ाई जाती है। समुदाय के महत्वपूर्ण संसाधन, इन मकतबों को आसानी से आधुनिक बना कर कक्षा 1 से 5 तक प्राथमिक विद्यालय के रूप में मान्यता दी जा सकती है। यहां उर्दू, हिन्दी तथा अंग्रेजी को समान रूप से पढ़ाया जाना चाहिये ताकि बच्चे प्राथमिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा भी आसानी से प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि इस्लामी शिक्षा की केन्द्र बिन्दु पवित्र कुरान और हदीस को भी दूसरे सामाजिक विज्ञानों, इतिहास, भूगोल और समाज विज्ञान के साथ शामिल कर ज्यादा दिलचस्प तरीके से पढ़ाया जा सकता है। मकतबों के अलावा प्रदेश में 2500–3000 अरबी–फारसी–उर्दू मदरसे हैं। यहां बच्चे 12 से 16 साल तक अध्ययन करते हैं। इनको आधुनिक बना कर मुख्यधारा शिक्षा संस्थानों के समकक्ष बनाया जा सकता है। समझा जाता है कि मकतब–मदरसा शिक्षा के बाद धार्मिक काम आसानी से मिल जाते हैं पर इन कामों में लगे लोगों को इतना कम पैसा मिलता है कि अपना जीवन चलाने के लिए उन्हें धार्मिक काम के साथ–साथ अन्य सम्मानपूर्ण रोजगार भी चाहिये।

प्रो. जाफरी ने कहा कि आधुनिकीकरण के बाद 5 साल के तहतानिया कोर्स को प्राइमरी स्कूल के बराबर सरकार द्वारा मान्यता दी जा सकती है। इसी तरह फौकानिया सार्टीफिकेट को मिडिल स्कूल के बराबर तथा 10 साल पढ़ने के बाद मुंशी या मौलवी पाठ्यक्रम को हाई स्कूल की मान्यता मिल सकती है। 12 साल पढ़ कर मिलने वाले आलिम को इंटरमीडियेट के बराबर मान्यता मिल सकती है। कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा 14 साल पढ़ाई के बाद दी जाने वाली अदीबे–कामिल उपाधि को मान्यता दी गई है। इसे और आधुनिक बना कर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा स्नातक डिग्री के तौर पर क्यों स्वीकार नहीं किया जा सकता है? सरकार द्वारा इसे सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होने के लिए स्वीकार किया जाना चाहिये। मकतब–मदरसा आधुनिकीकरण के लिए एनसीईआरटी व यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त इनका एक केन्द्रीय बोर्ड होना चाहिये। आधुनिकीकरण में भी इस बात की पूरी कोशिश होनी चाहिये कि शताब्दियों से चलने वाली धार्मिक शिक्षा में कोई कमी न आने पाये। सरकार मकतब–मदरसा के कम से कम आधे कर्मचारियों को वेतन आदि दे सकती है। हमारे मुदर्रिसों और धार्मिक नेताओं की सलाहियत में कोई कमी नहीं है और वे इंटीग्रल युनीवर्सिटी तथा यूनिटी कालेज जैसी आधुनिक संस्थायें चला रहे हैं। मदरसे और मकतब भी अपनी क्षमता बढ़ा कर आईटीआई व कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, प्रबंधन आदि के पेशेवर पाठ्यक्रम चला सकते हैं। मदरसों के खर्च के लिए जिले–जिले में फैली वक्फ संपत्तियों की आमदनी का एक हिस्सा देने का कानून भी बनाया जा सकता है। मदरसों में इंदिरा गांधी ओपेन स्कूल के केन्द्र भी खोले जाने चाहिये जहां से बच्चे आसानी से मुख्यधारा शिक्षा की मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। प्रो. जाफरी ने सवाल किया कि जब 1.5 प्रतिशत ईसाइयों के मिशन स्कूल देश में सभी लोगों के आकर्षण के केन्द्र बन सकते हैं तो 20 प्रतिशत मुस्लिम जनसंख्या द्वारा चलाये जाने वाले मकतब–मदरसे ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं?

मदरसा शिक्षा में सुधार

हिन्दी–उर्दू के लोकप्रिय साहित्यकार व सामाजिक कार्यकर्ता शकील सिद्दीकी ने 'मदरसों में प्राथमिक शिक्षा–इस्लाह के इम्कानात' पर अपना आलेख पेश किया। उन्होंने स्वीकार किया कि 1857 के विद्रोह की विफलता और उसके परिणामस्वरूप अंग्रेजों द्वारा मुसलमानों के भीषण दमन के कारण मदरसा

शिक्षा की सीमायें सिकुड़ी और उनके स्वरूप में भी परिवर्तन आया। हालांकि मदरसों ने इस्लाम तथा धार्मिक शिक्षा के प्रसार में अपना अमूल्य योगदान दिया पर समकालीनता से इसकी दूरी भी बढ़ी। इस मामले में 'दर्से निजामी' पाठ्यक्रम निर्माण की ऐतिहासिकता व उपयोगिता तथा औरंगजेब द्वारा अपने उस्तादों की आलोचना को भी भुलाया नहीं जा सकता है। मदरसा शिक्षा के पक्षधरों में दर्से निजामिया के प्रति व्यापक सहमति रही पर समय बीतने के साथ इसमें सुधार व असहमति के स्वर भी उठने लगे। लखनऊ में स्थापित दारूल उलूम नदवतुल उलेमा इसी असहमति का प्रतीक है। मदरसा शिक्षा के पाठ्यक्रम व पाठ्य सामग्री में परिवर्तन एवं उसे समकालीन जरूरतों के अनुरूप बनाने के संबंध में बराबर चर्चा होती रही है। इस विषय पर लंबी बहसें भी हुई हैं। जमाते इस्लामी के मदरसों का पाठ्यक्रम दर्से निजामी से अलग है। नदवा में प्राइमरी सतह पर हिन्दी–अंग्रेजी के अलावा कुछ दूसरे विषय भी पढ़ाये जाते हैं। मौलाना अबुल अली हसन नदवी का ख्याल है कि 'मदरसा वह कारखाना है, जहां कल्ब व निगाह जेहन व दिमाग ढलते हैं। मदरसा वह मकाम है जहां से पूरी कायनात का हिसाब होता है और पूरी इन्सानी जिन्दगी की निगरानी की जाती है।' मौलाना मरहूम, मदरसों को आलमे इस्लाम का बिजलीघर मानते थे। श्री शकील सिद्दीकी के अनुसार इस रोशनी में देखने पर मदरसे के तालीमी निजाम में तब्दीली की गुंजाइश अपने आप पैदा हो जाती है। मदरसों की खास पहचान यानी मजहबी तालीम में तब्दीली की हिमायत किये बगैर इसे देने के तरीके में तब्दीली की जरूरत है।

मदरसों की पढ़ाई में आधुनिक ज्ञान के विषयों के लिए जगह निकालना भी अपने आप में एक समस्या है। आलेख के अनुसार, 'प्राइमरी सतह पर यह और भी जरूरी है। हालांकि यह मुश्किल अमल है। इस सतह के बच्चों पर मजहबी तालीम का ही इतना दबाव होता है कि दूसरे उलूम की तरफ ध्यान कर पाना आसान नहीं है। बहुत जगह हिफ्जे कुरान पर जितना जोर होता है उतना अरबी भाषा सीखने पर नहीं। जबकि नदवा के पाठ्यक्रम के अनुरूप अरबी भाषा की तालीम का अमल प्राइमरी सतह से ही शुरू हो जाता है। इसके साथ ही अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, कहीं–कहीं गणित की भी इब्तिदाई तालीम दी जाती है।'

मदरसा शिक्षा को सामाजिक जरूरतों के मुताबिक ढालने में दीनी तालीमी कौंसिल के सांगठनिक प्रयास का शकील सिद्दीकी ने खासतौर से जिक्र किया। दीनी तालीमी कौंसिल, उ.प्र. के निसाबे तालीम के अनुसार, 'चुनानचे निसाबे तालीम इसी नुक्ताए–निगाह से मुरत्तब किया गया है कि मुसलमान बच्चे इस्लाम के बुनियादी अकायद, अखलाक, इबादत, मुआमलात, सीरते मुकद्दस सहाबा–ए–कराम, औलिया–ए–अल्लाह के हालाते जिन्दगी और तारीखे इस्लाम से जरूरी हद तक वाकिफ होकर एक तरफ पुख्ता और बेहतर मुसलमान बनकर उठें और दूसरी तरफ वे मुरव्विजा उलूम, हिसाब, हिन्दी, जुगराफिया, तमद्दुन और आम मालूमात से भी बेहतरीन दस्तगाह लेकर मकतब से निकलें।' इस दृष्टिकोण के अनुसार कौंसिल ने अपने निसाब में मजहबी तालीम के साथ ही प्राइमरी सतह पर अखलाकियात के साथ ही अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू भाषाओं के अलावा गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल जैसे आधुनिक ज्ञान के विषय भी शामिल किये हैं। कई विषयों के मामले में उसने उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा परिषद की पाठ्य पुस्तकों को अपने लिये स्वीकार किया है। नदवा ने भी परिषद की कई पुस्तकों को स्वीकार किया है। नदवा और कौंसिल ने, बल्कि जमाअते इस्लामी ने भी अपने पाठ्यक्रमों के लिए खासतौर पर कुछ किताबें तैयार कराई हैं जिनमें बच्चों की किस्सुलउंबिया खास है। मूलतः यह किताब अरबी में है और आमतौर से मदरसों में इसका उर्दू अनुवाद पढ़ाया जाता है। इस्लाम की तालीम, खिलाफते राशिदा, मिसाली हुक्मरां तथा उर्दू व हिन्दी भाषा ज्ञान की पुस्तकें खासतौर से काबिले जिक्र हैं। इनमें भी मौलवी मुहम्मद इस्माईल की कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाई जाने वाली उर्दू किताबें बेहतर पाठ्य पुस्तक का अच्छा उदाहरण हैं। मिलेजुले बहुधर्मी समाज के लिए इनकी विशेष उपयोगिता है।

हालांकि जमाते इस्लामी की कुछ किताबों पर एतराज किया जा सकता है पर प्राइमरी शिक्षा सहित तालीम पर उसका नजरिया भी किसी के एतराज लायक नहीं है। प्रो. खुर्शीद अहमद की 'इस्लाम का नजरिया ए तालीम' के अनुसार, 'तालीम सिर्फ तद्रीसे आम का ही नाम नहीं है। यह एक ऐसा अमल है, जिसके जरिये एक कौम खुदआगही हासिल करती है और यह अमल उस कौम को तश्कील देने वाले अफराद के एहसास व शुऊर को निखारने का जरिया होता है। यह नई नस्ल की वह तालीमो–तरबियत है जो उसे जिन्दगी गुजारने के तरीकों का शुऊर देती है और उसमें जिन्दगी के मकासिद व फरायज का एहसास पैदा करती है। तालीम से ही एक कौम अपने सकाफती व जेहनी विरसे को आइन्दा नस्लों तक पहुंचाती है और उनमें जिन्दगी के उन मकासिद से लगाव पैदा करती है, जिन्हें उसने इख्तियार किया हुआ है। तालीम एक जेहनी, जिस्मानी और अखलाकी तरबियत है और उसका मकसद ऊंचे दर्जे के ऐसे तहजीबयाफ्ता मर्द और औरतें पैदा करना है जो अच्छे इन्सानों की हैसियत से और किसी रियासत के जिम्मेदार शहरियों की हैसियत से अपने फरायज को अंजाम देने के अहल हों।'

कुछ लोग आज भी दीनी और दुनियावी तालीम के बीच इस लिहाज से फर्क करते हैं कि जैसे दुनियावी तालीम लेने वाला या दुनियावी लिहाज से सफल इन्सान, सच्चा मुसलमान नहीं रह जायेगा। श्री शकील सिद्दीकी अपने आलेख के अन्त में बड़ी साफगोई से इस दुविधा पर अपनी बात रखते हैं। उनके अनुसार–अच्छा या सच्चा मुसलमान बनने का यह मतलब कतई नहीं है कि मदरसे से फारिग हर जवान मौलवी, हाफिज, मुअज्जिन, इमाम, मुकर्रिर, खतीब या मुदर्रिस ही हो। वह अपनी सलाहियतों के मुताबिक किसी भी शोबे में जा सकता है। पिछले सालों में मदरसे से फारिग बच्चों ने जिन्दगी के मुख्तलिफ शोबों में अपनी बेहतर सलाहियतों का सबूत दिया है। लेकिन एक अच्छे शहरी, एक सामाजिक प्राणी तथा खासतौर से एक मुसलमान होने के नाते उन पर जो जिम्मेदारियां आयद होती हैं, और आज उन्हें जिन चुनौतियों का सामना है, उन्हें देखते हुए सिर्फ इस्लामी इतिहास ही नहीं राष्ट्रीय और सामाजिक विकास का इतिहास तथा प्रमुख स्थानीय भाषा की जानकारी जरूरी है। अंग्रेजी का ज्ञान उनमें अतिरिक्त सामर्थ्य पैदा करेगा क्योंकि आगे की समूची शिक्षा का दारोमदार प्राइमरी शिक्षा पर होता है इसलिये इसी सतह पर इस ज्ञान की गुंजाइश के इम्कानात तलाश करने की जरूरत है।'

खुला सत्र

आलेख प्रस्तुतीकरण तथा प्रस्तुतकर्ताओं से प्रतिभागियों के सवाल–जवाब के बाद सेमिनार के अन्त में एक खुला सत्र आयोजित किया गया। इसमें जहां मुदर्रिसों ने अपनी समस्याओं की बात की वहीं एनजीओ प्रतिनिधियों ने भी अपने सवाल व आशंकायें सामने रखीं। खुले सत्र के दौरान बीच–बीच में विशिष्ट अतिथि भी अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते रहे। खुले सत्र में कुछ सवाल विषय से हट कर मुस्लिम समाज की अन्य समस्याओं पर भी आये। एक महिला प्रतिभागी ने मुस्लिम समाज में लड़कियों की स्थिति का जिक्र करते हुए शिकायत की कि मदरसों में शिक्षा के बाद भी लड़कियों का व्यक्तित्व दबा–कुचला ही रह जाता है। इसके जवाब में बताया गया कि जेंडर पूर्वाग्रह केवल मुसलमानों में ही नहीं बल्कि हर मजहब मानने वाले लोगों में कमोबेश पाये जाते हैं। इसके अलावा घर का माहौल भी पढ़ाई पर असर डालता है। अगर घर में लड़कियों को दोयम दर्जे का माना जाता है तो शायद ही किसी प्रकार की शिक्षा इसमें कोई सुधार कर सके। इस्लाम में फतवों का सवाल आने पर विशिष्ट अतिथियों का कहना था कि फतवे किसी खास मामले में दिये जाते हैं जिनका हर स्थिति में थोपा जाना ठीक नहीं है। कई बार फतवों में भी इस्लाम की रूह पर गौर नहीं किया जाता हे। अगर शिक्षा की किसी किताब में चिड़िया या कोई और तस्वीर दी गई है तो उसे गैर–इस्लामी कहना गलत होगा। इस्लाम में किसी तस्वीर की पूजा करना मना है और केवल इसी तरह तस्वीर के इस्तेमाल को गलत कहा जा सकता है। विशिष्ट अतिथि इस बात पर भी एकमत थे कि पुराने उलमाओं ने दीनियात के

साथ अनेक अन्य दुनियावी इल्म भी सीखे थे और आज भी हमें अपने मुदर्रिसों, छात्रों तथा पूरे समाज को दीनियात के साथ बेहतर दुनियावी सलाहियतों से लैस करने की जरूरत है।

संक्षेप में कहा जाये तो नालन्दा, लखनऊ द्वारा आयोजित यह सेमिनार मुदर्रिसों, शिक्षा विशेषज्ञों तथा एनजीओ प्रतिनिधियों के बीच सेतु स्थापित करने के काम में काफी सीमा तक सफल रहा। हालांकि कुछ प्रतिनिधियों को मुदर्रिसों की सक्रियता थोड़ी कम लगी, पर उम्मीद की जानी चाहिये कि लगातार संपर्क से वे और खुलेंगे। मकतब–मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण से न केवल मुस्लिम समाज लाभान्वित होगा बल्कि यह भारत की प्रगति में भी अभूतपूर्व योगदान होगा। दुःख की बात है कि अपने जन्म के बाद से काफी लंबे समय तक ज्ञान–विज्ञान की प्रगति में अभूतपूर्व योगदान देने तथा मानव समाज को तरक्की की नई राहें दिखाने वाला मुस्लिम समाज अनेकानेक कारणों से वर्तमान समय में देश–दुनिया में निहित स्वार्थी ताकतों के निशाने पर है और मकतब–मदरसे भी इसका अपवाद नहीं हैं। खुशी की बात है कि मुस्लिम समाज इस चौतरफा हमले से पस्त हिम्मत नहीं है बल्कि जिन्दगी के सभी क्षेत्रों में नये जोश के साथ आगे बढ़ने की कोशिशें कर रहा है। अनेक मकतब–मदरसों ने आधुनिक शिक्षा पद्धतियों को अपना कर अपने छात्रों को दीन–दुनिया में बराबर तरक्की के मौके दिये हैं। हाल ही में मदरसे के एक स्नातक द्वारा आईएएस परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मुस्लिम नौजवानों में जोश की नई लहर दौड़ गई है। उम्मीद की जानी चाहिये कि नालन्दा जैसे संस्थानों द्वारा मकतब–मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण के प्रयास आगे आने वाले समय में और गति पकड़ेंगे। मदरसा कोर्सों को सरकार द्वारा मान्यता देने की मांग भी आगे आने वाले समय में सभी नागरिक समाज संस्थाओं को करनी होगी।

''मकतब–मदरसों में प्राथमिक षिक्षा का सुदृढ़ीकरण'' विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन सहभागी षिक्षण केन्द्र, सीतापुर रोड, लखनऊ में किया गया। सेमिनार का उद्देष्य मकतब–मदरसों की प्राथमिक षिक्षा पर कार्य करने वाली संस्थाओं एवं मदरसों से जुड़े जिम्मेदार व्यक्तियों के साथ उनके अनुभवों का साझा करना तथा मदरसों की दुनियाबी तालीम को मजबूत बनाने पर आपसी सहमति बनाना था। सेमिनार में आए लखनऊ विष्वविद्यालय के मानवषास्त्र विभाग के प्रो0 नदीम हसनैन, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली के डा0 मुजम्मिल हुसैन कासमी व डा0 जसीम अहमद, दिल्ली विष्वविद्यालय के नईमुल हसन एवं लखनऊ के लेखक एवं सामाजिक कार्यकर्ता षकील सिद्दीकी आदि ने अपने आलेख पढ़े। इसके साथ ही विभिन्न संस्थाओं एवं मदरसों से आए लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। सेमिनार में हुए विचार–विमर्ष एवं सवाल–जवाब में निष्कर्ष के तौर पर निम्नलिखित बिन्दु उभर कर आए –

- मुसलमानों की तरक्की के लिए मदरसों को आधुनिक बनाने की सख्त जरूरत है। मकतब–मदरसों में दीनी तालीम के साथ ही असरी तालीम अनिवार्य बनाई जाए।

- मकतब–मदरसों में षिक्षण की नई विधियां लागू करने व षिक्षकों को सेवा के पहले तथा सेवा के दौरान प्रषिक्षण देने की जरूरत है। इसके लिए मदरसा कमेटी को मदरसों के तालीम की बेहतरी के लिए काम करने वाली संस्थाओं के साथ मिलकर पहल करने की जरूरत है।

- समुदाय को राज्य और केन्द्रीय सरकार से छोटे मदरसों से लेकर कम से कम हायर सेकण्डरी स्तर तक सभी मदरसों को बिना षर्त मान्यता देने की मांग उठानी चाहिए ताकि इन मदरसों के स्नातक खुद को तथा पूरे मुस्लिम समाज को षिक्षा की मुख्यधारा में ला सकें।

- मदरसों की षिक्षा को गुणात्मक बनाने के लिए व आधुनिक षिक्षण विधियों के लिए षिक्षकों को अनिवार्य प्रषिक्षण देने पर बल दिया गया। मदरसा षिक्षकों को आवष्यकता आधारित प्राथमिक

स्तर पर प्रषिक्षण देना अनिवार्य बताया गया। षिक्षकों को कुषल, सक्षम, प्रतिबद्ध तथा परिणाम देने वाले षिक्षकों के रूप में तैयार करना स्वीकार किया गया।

- मदरसा पाठ्यक्रम को आधुनिक बनाने पर विषेष बल दिया गया। समता, समानता और न्याय पर आधारित नई सामाजिक व्यवस्था विकसित करना समाज की जिम्मेवारी है। अतः पाठ्यक्रम में ऐसे तत्वों को डालने की जरूरत है जिसमें सांस्कृतिक विविधता, राष्ट्रीय पहचान व एकता, विष्लेषणात्मक क्षमता बढ़ाने के साथ व्यक्ति की आत्मनिर्भरता सुनिष्चित हो।

- मदरसों से निकलने वाले तल्बा की जिन्दगी केवल पांच अरकान पर ही न टिक कर रह जाए बल्कि वह समाज में उत्पादक योगदान दे सकें व आत्मनिर्भर बन सकें तथा जिन्दगी को सुचारू रूप से चला सकें। इसके लिए मदरसों में व्यवसायिक षिक्षा की भी व्यवस्था की जाए।

- मकतब–मदरसों के मूल्यांकन की पुरानी प्रणाली की बजाए 'निरंतर एवं समग्र' मूल्यांकन की आंतरिक प्रणाली की अवधारणा विकसित करने पर बल दिया गया।

- सरकार को मकतब–मदरसा आधुनिकीकरण के लिए एन0सी0ई0आर0टी0 व यू0जी0सी0 से मान्यता प्राप्त एक केन्द्रीय बोर्ड बनाना चाहिए। मदरसों के खर्च के लिए जिलों में फैली वक्फ सम्पत्तियों को आमदनी का एक हिस्सा देने का कानून भी बनाया जा सकता है।

- मुस्लिम समुदाय को अपनी तरक्की हेतु जागरूकता लाने पर एक मत से सहमति बनी। विषेष कर मदरसा षिक्षा के प्रति मौजूदा दृष्टिकोण में बदलाव लाने हेतु बल दिया गया। जिससे मकतब–मदरसे आधुनिक षिक्षा के माध्यम से मुख्यधारा के साथ चल सकें।

नालन्दा स्टाफ की सेमिनार से प्राप्त सीख

सेमिनार में दीनी तालीम के साथ दुनियाबी तालीम पर जोर देने के लिए समझाया गया। सेमिनार के द्वारा हमें इस बात की पक्की समझ हुई कि हम मदरसे में प्राथमिक षिक्षा को बेहतर बनाए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। इसके लिए हमें अपना कम्यूनिकेषन स्किल अच्छा करने की जरूरत है।

- अब्दुल वहाब खान

मकतब/मदरसा कार्यक्रम को बेहतर और प्रभावी बनाने के लिए एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन सहभागी षिक्षण केन्द्र में दिनांक 30.8.2008 को हुआ। इसमें विभिन्न प्रान्तों से अनेक प्रोफेसर अनेक विष्वविद्यालय से आए।

इस प्रोग्राम में जितने भी विद्वान आए थे अपने–अपने खयालात पेष किए जिससे मदरसा एजुकेषन बेहतर हो तथा उनमें पढ़ने वालों बच्चों का मुस्तक्विल बने।

इसमें यह भी सीख बनी कि मदरसों में नवीन तौर–तरीकों को लगाते हुए तालीम दी जाए तो उनके सीख/समझ में वृद्धि होगी। चूंकि आज तरक्की का दौर है और हमारे देष का हर नागरिक तरक्की करे तभी देष की तरक्की सम्भव है।

- नसीम अहमद

सेमिनार से हमें सबसे बड़ी सीख ये मिली कि हम या हमारे समाज के बच्चे हिन्दी, उर्दू या दूसरी जुबाने चाहे जितनी अच्छी सीख लें लेकिन जब तक अंग्रेजी जबान नहीं सीखेंगे तब तक वह दुनिया में तरक्की नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अंग्रेजी जबान इंटरनेषनल जबान बन चुकी है। डा0 जसीम अहमद के लेक्चर से यह भी पक्की समझ बनी कि कुर्आन किसी भी जबान सीखने के लिए मना नहीं करता है मगर हमें अपनी तहजीब नहीं भूलनी चाहिए और खासकर मदरसों के बच्चों को दीनियात, उर्दू, अरबी के साथ–साथ अंग्रेजी जरूर पढ़ानी व सिखानी चाहिए ताकि मुस्लिम बच्चे भी लिखकर पढ़कर किसी लायक बन सकें और जमाने में दूसरे लोगों के कंधों से कंधा मिलाकर चल सकें। इसके अलावा और भी कई चीजें समझ में आई। खासतौर पर यह समझा और सीखा कि मदरसों में भी अरबी, दीनियात, उर्दू के साथ दुनियाबी तालीम देना बहुत जरूरी है।

- अहमद सईद

एक दिवसीय सेमिनार 30 अगस्त को लखनऊ के सहभागी षिक्षण केन्द्र में सम्पन्न हुई। जिसमें हमें बहुत सी बातों पर समझ बनी। जिनमें से कुछ निम्न हैं –

1. मदरसा बच्चों के बुद्धि स्तर तथा मुदर्रिसों के मानसिक स्तर के अनुसार कार्य करने की समझ बनी।
2. षिक्षा के बारे में इस्लाम के नजरिए के बारे में जानने को मिला।
3. मदरसों के लिए प्राथमिक षिक्षा में होने वाले अन्य कार्यों के बारे में जानने को मिला।

- जीनत वाहिद

सेमिनार पर बनी सीख

1. मदरसों के बच्चों को कोई भी सबक को रोल प्ले द्वारा पढ़ाने पर सीख बनी।
2. मदरसों में प्राथमिक षिक्षा में सुधार किया जा सकता है।
3. बच्चों के रूचि और मेयार के आधार पर षिक्षण कार्य किया जाए।

- अशफाक अहमद अंसारी

Papers Presented in Seminar

Role of Madrasas in enhancement of Education in India

Dr. Naimul Hasan

Sr. Lecturer,

Department of Arabic, University of Delhi

We are living in 21st century that is the age of advancement of knowledge and information technology. Each and every one is looking forward to get highest position in the society, as well as in private and government sectors. The importance of education is evaluated only as per the market demands, and the people choose only job oriented courses which have some value in the market.

In this phenomenon the Madrasa education is losing its importance. The rich families and well earning people send their kids to well furnished schools and colleges. Even Muslims do not care about the classical method of learning. They have no interest in getting basic knowledge of Islamic priciples, to understand Qur'an, Hadith, and the Shariah.

In fact only a very small number of people or some weaker sections of Muslim society due to their economic problems send their children to a Madrasa to get religious education. Even Muslims disgrace the graduates of Madrasas, because they are not so up-to-date to fulfill the needs of the society.

Nowadays the scenario is being changed. Madrasas are being discarded, targeted and the media is projecting its face as a centre of terrorism.

But in past, these Madrasas had been played a remarkable role in enhancement education and created a great history in this field. Let us have a glance on the role of Madrasas in imparting education not only among the Muslims but other sects of our society.

Earlier the Mosques and Madrasas remained the only institute of all sciences through out the Islamic era from the advent of Islam in Arab world, including the golden periods of the four Caliphs, Umayyad and Abbasid rulers extending to Spain, African countries, and Asia. Many scholars like Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Hanifa, Ghazali, Ibne Rushd, and Ibn-e- Sina were products of these Mosques and Madrasas.

The prominent historian P. K. Hitti describes in his famous book 'History of the Arabs': "The mosques in almost all Muslim towns served as important educational centres. When a visitor came to a new city he could make his way to the congregational mosque confident that he could attend lectures on Hadith". (There were assemblies in almost all Mosques where lectures were delivered by prominent scholars) … Not only religious but linguistic and poetical subjects were treated in these assemblies. Every Moslem had free admission to such lectures in the mosques, which remained until the eleventh century the extension school of Islam". [1]

[1] - P.K. Hitti : History of the Arabs pp. 412- 13, ST Martin's Press, New York, 1968.

He says: "The first prominent institution for higher learning in Islam was the Bayt al-Hikmah (the house of wisdom) founded by al-Ma'mun (830 a.d.) in his capital. Besides serving as a translation bureau this institute functioned as an academy and public Library and had an observatory connected with it" … But first real academy in Islam which made provision for the physical needs of its students and became a model for later institutions of higher learning was the Nizamiyah, founded in 1065-67 by the enlightened Nizam-al-Mulk, the Persian vizier of the Saljuq Sultans Alp Arslan and Malikshah and the patron of Umar al-Khayyam.

The Nizamiyah was established as a theological seminary (Madrasa), particularly for the study of the Shafi´i rite and the orthodox Ash´ari system in it the Koran and old poetry formed the backbone of the study of the humanities (´lm al-adab) precisely as the classics did later in the European universities".[2]

History of the Madrasas in India goes back to the advent of Muslims to the subcontinent**.** They played an important role in the eco-cultural life of the Muslim society. In the medieval India, they used to provide with the manpower to the government to run its huge and vast machinery. A chain of these Madrasas were spread in the length and breadth of the country. They were instrumental in imparting education to the masses. They were marked with the secularism in their nature. This, including with other characteristics of the madrasas, attracted a good crowd of the children even from the non-Muslim majority. This situation continued up till late 19th century. The luminaries like Raja Ram Mohan Roy, Dr.Rajendra Prasad and Dr.Sachdanand Sinha and thousands of others got their elementary education in madras.

The situation started changing in 19th century when some critical problems engulfed the Muslims of the sub-continent. On the one hand, the hegemony (domination) of the Muslim dynasty which had been ruling the country for centuries came to an end and, on the other hand, the English, conquering the land, had begun to consolidate their empire. Muslims were in a dilemma, not been able to decide what to do. As the English put an end to the traditional education system, they divided the education into two categories: religious and non-religious. This made the ulama worried about the preservation of the religious as well as cultural identities. The ulama responded to the situation in two ways: firstly, they tried to tackle this impasse through violent means in uprising of 1857 but it resulted in disastrous consequences; secondly, sensing the change in the need and nature of the time, they did their best to open a series of madrasas at a number of places first in UP and then all across the country. Thus, a network of madrasas got established in the country.

The English after establishment of their empire introduced a new system of education to change the existing system of education in mosques, madrasas, and guru vidyapeaths at that time.

The credit of introducing prototype of education, today known as the English/Secular Education System goes to Lord Thomas Babington Macaulay who came to India as Viceroy of the British India Company. The purpose of introducing this system, in Macaulay's own words, was: "So that a generation may arise, which is Indian in birth and English in

[2] - ibid p. 410

thought." In other words, it aimed at consolidating the British Empire in India. Contrary to that, the ulama made an effort to establish an *apolitical empire* through setting up a network of madrasas across the country as a movement of Dini Madaris.

When India got its freedom, after a long struggle of National heros to ouster the English rulers from the country, and the subcontinent divided into two; India and Pakistan, the system of education remained same.

The situation didn't change after the Partition. When the All India Muslim Majlis-e-Moshawarat, the biggest movement of the Indian Muslims after the Independence, was launched, the ulama participated in it in a large number but they have gradually been marginalized and, thus, become ineffective. This can be seen as the consequences of the introduction of new education system by Macaulay in the country. It has created not only the dichotomy of religious and secular education but also raised the status of English to the language of the ruling elite and the educated ones. In this changed scenario, the madrasa graduates found themselves at the periphery of the day-to-day life though they have been playing important roles in every walk of life throughout the history.

Now the government is trying to do some reforms in Madrasa Education System, but it is not like that the Madrasa reform is only the government agenda. The issue has been in debate in the Muslim civil society for long time, though it has a diametrically different approach to the matter. The coming up of the Nadwa madrasa itself symbolizes this concern on the part of the ulama itself. After Independence, the experiments in the curriculum of madrasas related to the Jama'at-e-Islami and Ahl-e-Hadis stand testimony to the fact. The madrasa is a specialized institution providing Muslims with specifically 'religious' education and transmitting the Islamic scholarly tradition.

Thanks to the reforms done so far in some madrasas, the visibility of the madrasa graduates in the secular spaces like government universities, colleges, offices has considerably increased. Being exposed to both the regimes of education, they are at an advantageous position to criticize and demand for changes in the madrasa curriculum.

Unlike in the past, a good number of madrasas have come up for girls' education to make them trained as 'alimas (women scholars) that is a new development of the Muslim society. Currently, the madrasas are outside the purview of state education departments**.** The curriculum is not monitored or guided by these departments. Therefore, many privileges and incentives, which the government provides to regular schools to ensure kids enrolment, are not extended to madrasas. Madrasa education turns out to be less interesting and quite ineffectual. Central and state governments have betrayed a big chunk of Indian population by neglecting the education of these low-income group Muslims. Their policies have ensured these groups live in ignorance and poverty forever.

While we continue to address some of the real and genuine problems and issues that Islam faces worldwide as a religion, we should do our best to bring Indian Muslims into the mainstream, impart them with right education and skill sets, so that they can avail the jobs and opportunities this country has opened up.

One of the ways to bring the Indian Muslims into the mainstream is by giving them the same education that other kids get. Along with Religious teachings regularly in Madrasa's Nizamiyah system we can adopt some different aspects of mainstream education. The mainstream education will involve teaching different languages, Social Studies, Sciences and Mathematics and computer in a proper channel.

Now we have to do some amendments in our present curriculum to build up a full-fledged system of education which will impart religious as well as scientific educations to provide equal opportunities to madrasa graduates to stand neck to neck of the other native brothers and sisters in all fields.

If we are very interested to change the existing system of Madrasas education we have to adopt the new methods of teaching, taking major steps of new mechanism of modern institutions. The teachers, Muallimin and Muallimat should be trained either through pre service training or in-service training. We have to consider again and again adopting the government's agenda for centralization of Madrasas in India.

We request the State and Central government to recognize all Madrasas unconditionally to give them the status of at least higher secondary schooling, so that the graduates of these Madrasa could bring themselves and the whole Muslim society in main stream.

NEED BASED INSERVICE TRAINING OF MADRASA TEACHERS AT ELEMENTARY LEVEL OF EDUCATION

M H Quasmi

Overvew

"Madrasa is an institution of learning, where Islamic sciences including literary and philosophical ones are taught" (Encyclopedia of Islam - Lei den E.J.Brill). The aim of Madrasa education is to inculcate the belief and practice of Islam among its followers and guide them to follow Kuran and traditions of the Prophet. Being the lifeline of Muslim society madrasa is the real foundation of Muslim education in India. But in absence of clarity of vision about the present day economic and social needs of Indian Muslims, madrasa managers failed to play a positive role in the scheme of their education and preferred to keep the community subjugated under medieval psyche for their vested political interests. (R.Upadhyay). though the history of madrasa, dates back to the establishment of Delhi Sultanate in 1206 A.D. Initially its principal function was to train personnel for government service (Encyclopaedia of Islam) and accordingly curriculum was formulated to cater the administrative needs of Muslim rulers. Gradually with the patronage of these rulers it was extended to different parts of north India (Ahmad, Manzoor). The role being played by madrasa education system in India was reflected in the enthusiastic participation during the two-day national seminar (March 29-30) held at the Jawaharlal Nehru University (JNU). While it was accepted that the madrasa education system has produced some scholars of international fame, it was also pointed out that majority of *talaba* remains deprived of job opportunities. At the same time, attention was also paid to the fact that only Madrasas should not be held responsible for the weaknesses the country's education system is suffering from. The government schools reaching out to poor people in rural areas can from no angle be held to be centers of ideal means of education. It was also pointed out that a negative image held about Madrasas was not absolutely correct. There are quite a few Madrasas in the country, where courses in computerization and other modern skills were being imparted. It was felt that while it is important take measures towards enhancing standards of education offered at Madrasas, in-service training of the teachers working in Madrasas is needed. Daresh (1987) reviewed 160 studies dealing with participant's preferences for training topics and desirable content for staff/teachers development and found that staff development/in-service education is viewed as more effective when its content is based on the participants self reported needs.

Objectives

In-service training may used for training teachers within a specific programme and period of time within Madrasa education system. In-service training can be effective methods for helping teachers develop skills and knowledge necessary to become strong members of a system. For this NEED BASED INSERVICE TRAINING OF MADRASA TEACHERS is emphasized to be followed AT ELEMENTARY LEVEL OF EDUCATION with following objectives:

1. To produce skilled, competent, dedicated, productive teachers with in-service training programmes through appropriate and adequate training measures at Primary level of Madrasa education.
2. To promote needs driven skills development interventions informed by the Workplace Skills Plan.
3. To appreciate the importance of assessing training needs of teachers and trainers systematically before organizing their training.
4. To understand different areas of training needs.

Needs Assessment

The term 'need' has been used to denote the gap existing between the current status and the desired one or the required level of competencies. In case of Madrasa teachers it stands for gap existing between teachers present knowledge in their subject and their teaching proficiency on one hand and level of teaching proficiency or methods of teaching (traditional/child centered) on the other.

In India, it has generally been observed that the topics for training are selected by people other than those for whom the in-service training is organized. The in-service programmes rarely address to teachers' individual needs and concerns. Therefore, when Department of Teacher Training and Non Formal Education (IASE), Jamia Millia Islamia, New Delhi initiated in-service training for Madrasa teachers, first of all it surveyed 380 Madrasas of Delhi and their teachers' need for training. About 1500 teachers responded to the questionnaires sent to them. Some need based questions were asked as follows:

1. In which discipline do you like to gather more information?
2. What is your area of interest?
3. In which area do you want more training?
4. Which subject do you teach?
5. List out the topics whose transaction seems to be difficult for you?
6. Do you prepare/use teaching aid?
7. Do you want your skill refinement in using technology?
8. Write down your expectations of this training programme.

Area of Need

On the basis of teachers' responses following broad areas were identified and materials of training were prepared accordingly:-

1. Madrasa administration – including office management and book keeping.
2. Philosophy of education – including Islamic philosophy of education.
3. Psychology of education specially child psychology
4. Education and society
5. Curriculum development – different concepts and methods of developing curriculum.
6. Different Methods of Teaching
7. Lesson Planning in different subjects
8. How to give assignments
9. Evaluation – methods of framing questions and their evaluation

10. Computer training
11. enrichment content from the selected topics from Languages, Math, Environmental Studies, up to elementary level and Jurisprudence (Fiqha), Interpretation (Tafseer) and Traditions (Hadith) at higher level.

    The details of topics can be seen in presentation of Mdrasa Nisab2

Different Methods of Activity Based Teaching for Teachers Teaching up to Elementary level

A virtual classroom environment was created to impart teaching with different types of activity and using hands on experiences in the classroom. A detail discussion is made in the presentation of Taleemi Sargarmi.

Feed Back

The teacher educators and the supervisors were assigned to observe at least one lesson of each trainee at their respective Madrsas and report coordinator to make the programme more productive for the coming batches.

Voluntary in-service training

This is meant for teachers of Madrasas without compulsory in-service obligation to any institution, as they do not have any official obligation to receive any in-service training. Rather Madrasa administration does not want to spare their teachers for such trainings. So it becomes obligatory for trainers to convince the teachers for the training.

Roles and responsibilities of the supervisor/mentor

i. Liaise with the trainee with a view of determining his/her training and developmental needs;
ii. Plan and manage training and development of the trainee in a way that is consistent with the needs of the department as well as the development plan;
iii. Demonstrate a willingness to provide guidance and assistance to the trainee;
iv. Provide meaningful training or developmental opportunities for the trainee;
v. Participate in the final assessment of the performance and achievement of the trainee; and

Roles and responsibilities of the trainees

The trainees will ensure that he or she:

i. Participates fully in determining (with his or her supervisor/mentor) the training and development needs.
ii. Plans and manages (with his/her supervisor/mentor) learning and development in a way that is consistent with the needs of the department, as well as his/her development plan;
iii. Demonstrates the willingness to grow and learn through work experience

iv. Takes full advantage of the training and development opportunities available to him/her.
v. Participates in induction and orientation programmes as arranged by the department
vi. Cooperates fully with the supervisor/mentor assigned to

References

Encyclopaedia of Islam, New Edition, edited by P.J. Bearman, Th. Bianquis, C.E. Bosworth, E. van Donzel and W.P. Heinrichs.

Ahmad, Manzoor, Islamic Education: Redefinition of Aims and Methodology, New Delhi: Genuine Publications, 1990.

R.Upadhyay, MADRASA EDUCATION IN INDIA**-** *Is it to sustain medieval attitude among Muslims?*

NCERT, Self Learning Material for Teacher Educator, vol. I

NCERT, The Reflective Teacher

MADARSA EDUCATION IN THE MODRN AGE

By

Dr. JASIM AHMAD

Lecturer, Department of Teacher Training & Non Formal Education (IASE)

Faculty of Education, Jamia Millia Islamia, Jamia Nagar

New Delhi, India. Pin Code-110025,

Contact No. 9213760821.

E-mail: jasimjamia@gmail.com

jasim_ahmad@yahoo.co.in

Mailing Address: **As above**

The author has published many articles and research papers in different journals and presented papers in National & International Seminars in Education and Applied Psychology. His areas of interest are Science (Bio) Education, Educational psychology, Biopsychology, Value Education, Environmental Education and problems and issues of Education in India. He was a Fellow Member of United Writers Association of India (FUWAI). He is a life member of the AIAER and AIATE.

MADARSA EDUCATION IN THE MODRN AGE

Abstract

Globalization and Privatization has influenced all walks of life including Madarsa Education. Madarsa education and its curriculum are required to be dynamic, as the society is dynamic. The consensus and priorities of the Muslim Community, individual and the nation as a whole should be reflected in the curriculum. Madarsa Education is required to play five important roles i.e. (i) Religious Role (ii) acculturating role (iii) combative role (iv) liberating role and (v) integrative role**.** Considering the changes in national and global scenario due to globalization, privatization and various other factors, this paper proposes a model for Madarsa Education. Transactional strategies, methods of evaluation and training of madarsa teachers have also been discussed in the paper.

INTRODUCTION

Madarsa education is required to be responsive to the needs and aspirations of the muslim community in particular and society in general, that undergoes a change with the passage of time. This implies that the madarsa curriculum has to be dynamic, to suit the changing needs of the muslim community. The consensus and priorities of the muslim community, individual, and the nation, therefore, be suitably reflected in the curriculum.

Thrust areas of the changes in madarsa curriculum are **(i) Objectives (ii) Content Organization (iii) Process of Education and (iv) Pupils Evaluation**. Today, the development of creative and independent thinking ability invariably finds a place in the objectives of the curriculum. There was a time when science and mathematics were not compulsory subjects in the school curriculum. But nowadays these form an integral part of the curriculum at all stages of school education. Following the Indias' Education Commission Report (1964-66), greater emphasis in the curriculum was given to activities related to work experiences as a part of general education. Again at higher secondary stage, vocational education was given special importance. These examples indicate that the curriculum is dynamic in nature.

Madarsa education products should be prepared in such a way that after passing out madarsa they should be **two-in-one** i.e. **having sound knowledge, understanding and practitioner of ISLAM** as well as **having the capability to face the challenges of society and should be able to cope up with the competitive environment created by non-madarsa products i.e. school products**.

NEEDS & ASPIRATIONS

We have a cherished desire to develop a new social order based on equity, equality and justice. We need to preserve our cultural heritage and strengthen national identity and unity in order to counter a variety of divisive forces such as regionalism, casteism, and linguism etc. There is a need to have emphasis on character building, respect for constitutional obligations, promotion of global perspectives, protection of environment, conservation of natural resources, observation of small family norms etc. Madarsa education is required to be such which can play five important roles effectively and efficiently. These are **(i)**

Religious role (ii) Acculturating role (iii) Combative role (iv) Liberating role and (v) Integrative role. The religious role implies that the products of madarsa education should have sound knowledge, understanding and practitioner as well as dayee (who invite and draws others to Islam by his words and actions) of Islam. The acculturating role implies refining perceptions and sensitivities so as to enrich our culture and to promote national cohesion. The combative role implies that there are certain destructive tendencies within the individual and destructive forces within the society, which need to be fought against. The liberating role envisages that the child needs to be liberated from ignorance, superstition and from oppression etc., while the integrative role means integration of the child with the society and the world.

COMMON CORE

To promote national integration and the cultivation of values as enshrined in the constitution of India, National Policy of Education (1986) identified ten common core components for school education. It was visualized that in their transactions, emphasis would be placed on instilling nationally shared perceptions and values. These form the core component even today and they are of course essential for the younger generation to imbibe and to be a part of the ideal citizen's personality. These ten core components were made obligatory for all schools in the country-

i. History of India's Freedom Movement.
ii. Constitutional Obligations.
iii. Content essential to nurture national identity.
iv. Indian common cultural heritage.
v. Egalitarianism, democracy and socialism.
vi. Equality of the sexes.
vii. Protection of the environment.
viii. Removal of social barriers.
ix. Observance of small family norms.
x. Inculcation of scientific temper.

In the new changing national and global scenario as a result of globalization, some more newly developed areas may be included in the common core of school curriculum that requires to be the essential part of the personality of the child. These are necessary for every individual to have successful career and a prosperous and peaceful life. These may bring peace & harmony at individual, family, society, national and global level. These are-

xi. Stress: Concept, Cause and Management.
xii. Peaceful Conflict Resolution and Fair Negotiations.
xiii. Information and Communication Technology (ICT).
xiv. Human Rights and Duties.
xv. Protection of Minorities and weaker sections of society.
xvi. Leadership and Nation Building.

These 10 + 6 (as mentioned above) core components should be added in the madarsa education curriculum in addition to its primary concern i.e. emphasis on the development of

religious values, development of knowledge and understanding of Islam and providing education in various branches of Islamic education like Quran, Hadith, Feqah, Hafiz etc.

A model (see appendix, Figure-1) is being proposed for Madarsa education entitled "Madarsa Education Curriculum: A Model". It depicts the three layers of the madarsa curriculum comprising of core, mantle and crust. The core is further divided into inner core, middle core and outer core. Inner, middle and outer core refers to the components of curriculum related to Islamic education, individual & social significance, and national significance respectively. Objectives of madarsa education may be framed as per the religious, individual, social and national needs in the present age of globalization, privatization and social imbalance. Mantle refers to the division of streams of study as per the interest, aptitude and abilities of the learners, which has to be decided after ten years of education i.e. after Fauqania (equivalent to Xth standard) or at Maulvi level (higher secondary level or class 11^{th} and 12^{th}). The crust depicts the necessity of Vocational Education and Training for all the needy students to make them self-dependent as soon as they complete their higher secondary education/maulvi. This vocational Education and Training may not be compulsory for all students but it should be available to all, especially those students who belongs to the lower, lower middle and middle class families, as this will cater the needs of this class the most. Two years of quality vocational education and training will make them self-employed and they will be able to support their families provided that the vocational courses being provided are employment oriented and society need-based. The circular core, mantle and crust are surrounded by a square shaped boundary that depicts the role of the teachers and educational administrators. Teachers and Educational Administrators are the heart and soul of the educational process, quality and output. They require to be efficient, honest and having a kind of dedication in them. They should be given pre-service training as well as in-service training at regular intervals to acquaint them with new and modern findings and development in the field of their work. Three main components of the curriculum i.e. objectives, transactional strategies and evaluation must be framed, planned and executed in such a way that can nurture all the three domains of educational objectives – cognitive, affective and psychomotor.

TRANSACTIONAL STRATEGIES

The traditional modes of curriculum transaction do not cater for the development of different abilities and skills in a balanced manner. Although, the list of objectives includes development of independent thinking, originality, creativity, productivity, critical thinking, scientific temper etc., in practice little efforts is made to inculcate these skills and abilities and thus no remarkable change is observed in the young generation on these aspects of personality. Most widely used style of teaching is transmissive or expository, which puts premium on memorization rather than independent thinking. It places the teacher at the transmitting end, and the students at the receiving end, and so, the delivery system is devoid of interaction between teacher and students.

National Curriculum Framework for School Education-2005 (NCERT) has visualized a change in teachers' role from that of mere transmitter of information to that of facilitator. It may be incorporated in madarsa education. In this approach teachers act as facilitators who encourages learners to reflect, analyze and interpret in the process of knowledge construction. It revolves round the constructivism in which teachers have to perform in such

a way that students can construct their own knowledge. In this perspective, learning is a process of the construction of knowledge. Learners actively construct their own knowledge on the basis of materials or activities presented to them (experiences). These include healthy teacher-student dialogue, collection of materials, individual and group activities, demonstration and experimentation, project assignment, play way activities / educational games, educational excursion, role playing and dramatization, group discussion, conversation, inductive-deductive teaching, problem-solving, discovery-learning etc. The logic behind these modes of transaction is providing learners hands-on-experiences so that they may construct their own knowledge in their own pace and as per their own ability. It is commendable and fantastic approach, if used honestly, can change the scenario of madarsa education and the young minds.

EVALUATION

The traditional pattern of examination lays more emphasis on written than oral communication. It tests only lower level of mental ability like memory, knowledge etc, rather than the higher order of mental abilities like independent thinking, creative thinking etc. It is more suitable for academic subjects than the practice-oriented subjects like work experience and physical education. It confirms itself to the testing of cognitive abilities and ignores the affective aspects of personality. Moreover, there are serious reservations about the reliability and validity of examination works. Its relevance required to be enhanced.

Internal, 'continuous and comprehensive evaluation' is the concept developed for this purpose. Internal evaluation to be conducted by the teachers will facilitate the use of varied techniques of evaluation including oral examination. The system of continuous evaluation will ensure extensive coverage of syllabus on the one hand, and that of different kinds of objectives on the other. This will make the use of a variety of assessment techniques possible. The comprehensive evaluation will make it possible to take care of the affective and psychomotor aspects in addition to the cognitive aspects of personality.

INSERVICE TRAINING OF MADARSA TEACHERS

For efficient and effective teaching and learning process, it is essential to train all madarsa teachers, especially those who are newly recruited. Steps may be taken by Madarsa Education Boards to train their teachers as well as NGOs and Association of Madarsas at regional and national level. The training of madarsa teachers should focus on the following themes:

- Madarsa curriculum and reading material (text books) development and evaluation
- Method of teaching or transactional strategies especially learner oriented innovative approaches and methods
- Students' evaluation techniques
- Quality question paper development
- Research in madarsa education and comment on findings
- Psychology involved in teaching and learning
- Training in ICT
- Integration of content with community, society and the nature
- Life skills
- New emerging areas of content and methods of education

CHALLENGES & MEASURES TO MEET THEM

Globalization and the ICT have opened multiple ways of free accessibility to knowledge. This is an age of information technology and knowledge explosion. Not only knowledge is growing with exponential rate but also many of the existing knowledge are becoming obsolete with time. This has put double challenges to education. Now it is not possible to provide all relevant information of any area of study through formal education (curriculum) but the only option the formal education has to train the learners in such a way that they **learn the art of knowing themselves**. That is why in place of providing information the emphasis should be on **knowledge creation, creative thinking and independent analysis**. The first pillar of education as advocated by Delor's commission; **'learning to know'** has become true and relevant in the present scenario.

In the present globalized world, knowledge is considered to be the major source of empowerment. Knowledge is the most important tool to govern the market economy. Only those communities, society and the nation will lead the world, which understand the dynamics of knowledge and create a true knowledge society. This is the reason that our intellectual and visionary former president APJ Abdul Kalam has thought out and pleaded to make India a knowledge superpower by the year 2020 so that it can lead the post modern world of 21st century in a forceful intellectual way. This is possible only by developing a kind of national system of education that strives for excellence and is capable to provide quality education of international standard or even better than that. This requires excellence, competence and commitment in our teachers too. This is possible by reforming the madarsa and school curriculum to suit the global challenge, teacher education curriculum to develop excellent and competent teachers, honesty at all levels of education and proper place of teachers in the society, as they are the real builders of the community, society and the nation.

REFERENCES

- Caine, R.N. and Caine, G. (1991), Making Connections: Teaching and Human Brain. Alexandria, NA, Association for Supervision and Curriculum Development.
- Education Commission, (1964-66), Ministry of Human Resource Development (Education), Government of India.
- NCERT, National Curriculum Framework –2005, New Delhi.
- Rao, Digumarti Bhaskar, (1996), National Policy on Education, Vol. 1 & 2, Anmol Publication Pvt. Ltd., New Delhi-11002
- Terhart, Ewald (2003), 'Constructivism and Teaching: A New Paradigm in General Didactics', Journal of Curriculum Studies, 35 (1), pp.25-44.

Appendix:

Figure 1: Madarsa Education Curriculum: A Model

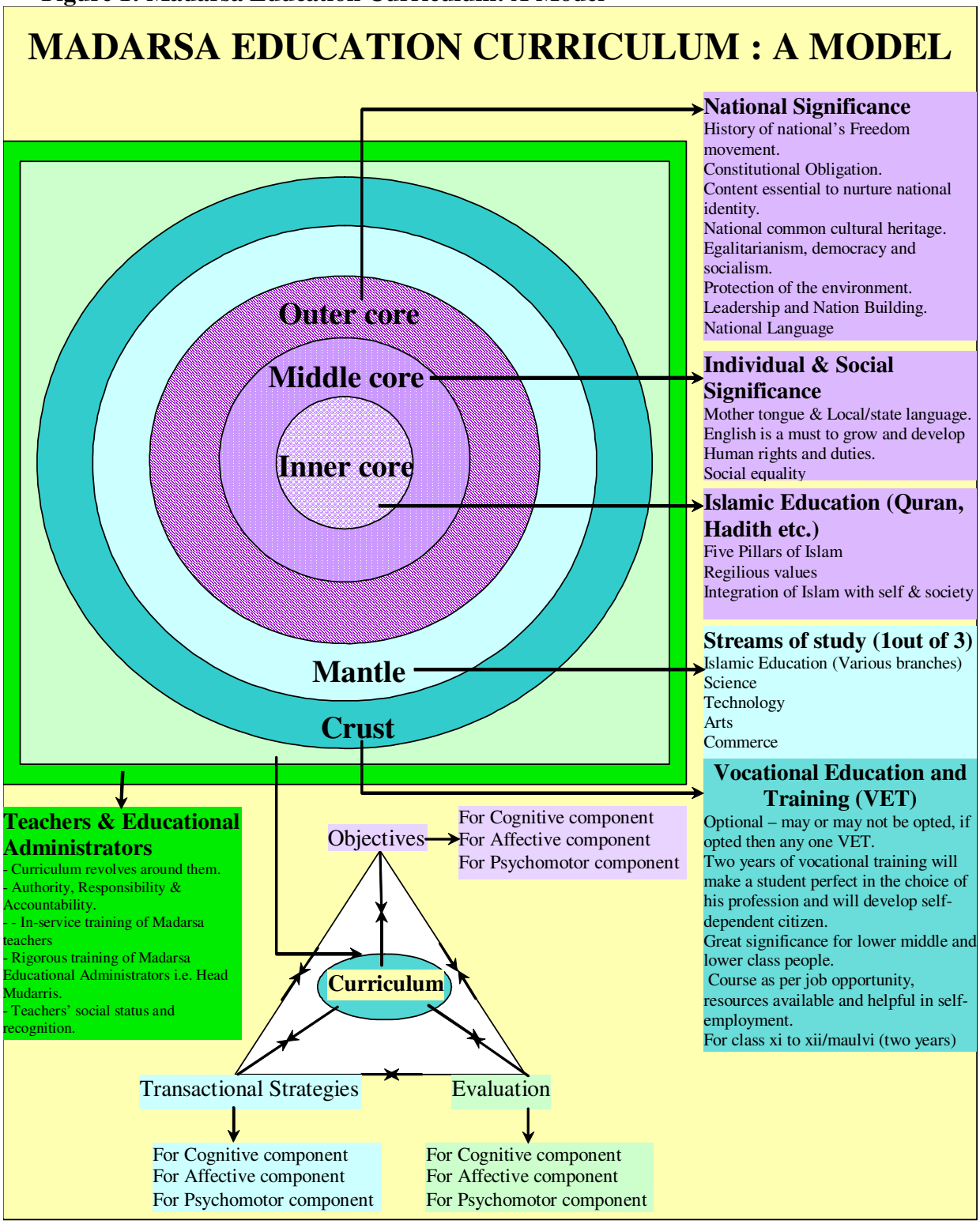

MODERNISATION OF MAKTAB AND MADARSA : INDIAN PERSPECTIVE

Prof. S.S.A. Jafri
Giri Institute of Development Studies, Lucknow
E-mail: jafri_ssa@rediffmail.com, Mobile: 9335806198

In 1835 Macaulay evolved to create altogether new education system in India rather than supporting the traditional education system which was prevailing in India in the form of Pathshala and Madarsa. The objective was to produce 'clerks' through English education in order to serve the East Indian Company. Through out the medieval period Madarsa system of education was producing the qualified youths who were serving the state may be in office, courts, Tehsils, police, hospitals, etc. The medium of education was generally Persian or Urdu and it was the official language in most parts of India. After the British occupation in India the scientific advancement of knowledge was carried forward through English and then after Independence by both through English and Hindi. Madarsas were kept aloof from modern English system of knowledge, as it was a wide perception that missionaries whose language was English may convert the masses, which was true in many cases. Sir Syed Ahmad Khan was considered the British agent. A great Reshmi Roomal movement during 1920s was launched from Deoband to chase the Britishers from India, but somehow it was unsuccessful. Even after independence till late recently the perception in and around Madarsa was that the modern education for Muslims is religiously and morally harmful. When the fact is that after industrial revolution the entire scientific knowledge is governed by the West which can reach us only through English and Western system of education.

It is not that Madarsas are spared from modern education but they are taught in Urdu and Persian which are practically no more official languages. Thus their qualified youths are unfit to be utilized in Hindi and English medium employment markets. If we go through the Madarsa syllabus we find that almost all the subjects are taught there with extreme seriousness and discipline, but there is a problem of medium of instruction and their recognition equal to formal education system. Maktabs and Madarsas are the backbone of education of the community and nations as a whole which are run by the community voluntarily and with great spirit. Traditional educational institutions of Maktabs and Madarsas are to be modernized and recognized by the government to become the media of modern education along with their traditional role in order to bring them in the main stream. As per estimate in U.P. alone about 30,000 Maktabs are run where limited reading of Holy Quran, knowledge of Urdu and elementary social science and mathematics is taught. These Maktabs should be considered as educational assets and can easily be modernized and recognized to primary schools from Class I to V. Three languages, i.e., Urdu, Hindi and English are to be taught equally, so that students may be able to cope up the higher classes after primary education. Quran and Hadith which are the core of Islamic teachings should be taught under Social Studies, History, Geography and Sociology through Urdu, Hindi and English mediums in an interesting manner.

There are about 2500 to 3000 Arabic-Persian-Urdu Madarsas in U.P. where students spend upto 12 to 16 years on studies, which all of them can be modernized and recognized as institutions of learning equivalent to institutions belonging to mainstream. Upto middle level of education training in various handicrafts should be made compulsory as non-traditional course, besides ITIs with Maktab-Madarsas, so that those students who don't

want to go for further education may not be deprived of gainful employment. It is understood that getting employment as clergy is quite easy but it is not even half of minimum gainful employment. It means that a clergies has to compensate his income by taking up some respectable employment in between prayers as 6 to 8 hours are already at his disposal to work.

Tahtania is 5 years course which should be recognized after modernization by the government equivalent to primary school. Fauqania certificate is given after 8 years of learning after 3 years of Tahtamia, which should be modernized and after it government should recognize it equivalent to middle school for all practical purposes. For Munshi or Maulvi in all 10 years education is required, which is after 2 years education of Fauqania, which also should be modernized and after that government must recognize it as High School. For Alim course 12 years are required which is after 2 years of Mushi or Maulvi needs to be modernized and recognized equivalent to Intermediate. Adeebe-Kamil is full 14 years course, i.e., after 2 years of Alim which is already recognized by few Universities, why not it should be further modernized and UGC should recognize it as a bachelor's degree and government should approve it for all competitive professional examinations. Fazil is 16 years course after 2 years of Adeebe-Kamil, very few Universities recognize it, needs to be further streamlined and recognized by the UGC as equivalent to Post-Graduate.

Now the question is that who would modernize these traditional courses which are taught in Maktabs and Madarsas. There should be a central board of education of Maktabs and Madarsa which should have recognition by NCERT and UGC where top national level educationist from both streams of traditional (representing all sects) and modern education must prepare the syllabus and publish the course material. There should be a serious effort that in no way the theological part of the course should be undermined for which the Maktabs and Madarsa stand since centuries. At least 50 per cent of the academic and administrative staff must be supported by the government.

Those modernized Maktabs and Madarsas with capacities should be allowed and financed to start ITIs and professional courses (computer, engineering and management) respectively. Examples are there that our Madarsas and clergies are running the best modern educational institutions like Integral University and Unity College, etc. In the mean while the board of National Institute of Open Schooling (NIOS), New Delhi should identify few Madarsas in each district and establish its centres in order to lure students of Fauqania, Munshi, Maulvi and Alim to appear in High School and Intermediate examinations. Not only the Madarsa students but those neighbouring boys and girls who are not able to attend the Madarsa, school and college would be benefitted by appearing in the examination. Circumstances change, it is found that sometimes boys and girls who are discouraged in one educational system get successful in another educational system.

There is an enormous Waqf property in every district which should be streamlined and Mutawallis should be encouraged to divert the Waqf resources to the cause of education. Special orders should be passed that the Waqf properties which are used as shops, residence or in other activities would be converted for educational purposes on priority basis as and when Mutawalli proposes to do so. Through such orders it should also be made clear that all the Waqf properties which are not specified by the owners, would be treated as Waqf for education only.

मदरसों में प्राथमिक शिक्षा – इस्लाह के इम्कानात

• शकील सिद्दीकी

यह व्यापक में स्वीकार किया गया है, तथ्य है कि व्यक्ति के जीवन में प्राथमिक शिक्षा अत्यन्त महत्व रखती है। इमारत की तामीर में जो अहमियत बुनियाद की होती है। तक़रीबन उतनी ही अहम होती है, प्राइमरी तालीम, व्यक्तित्व के निर्माण में, बौद्धिक विकास व हर हाल जिसका अनिवार्य हिस्सा होता है, इस तालीम की सबसे महत्वूपर्ण भूमिका होती है। यही वजह है कि एक ही समाज में अलग–अलग शिक्षा पद्धतियों से आये लोगों के सामाजिक व्यवहार–आचरण, रहन–सहन, समकालीन घटनाओं के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं तथा ज्ञान के प्रति उनकी उत्सुकता के अनुपात भिन्न होते हैं। शिक्षा पद्धति के चुनाव में सामाजिक हालात घरेलू परिस्थितियां तथा भविष्य के लक्ष्य का निर्धारण आम तौर पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। शिक्षा पद्धति के चयन में वाल्दैन और बच्चे की इच्छा शामिल हो, ऐसा कतई जरूरी नहीं है। कई बार यह चयन मजबूरी के तहत भी होता है। तमाम शिक्षा पद्धतियों के समान मदरसा शिक्षा पद्धति भी इन सच्चाईयों के प्रति संवेदनहीन रवैया रखती हैं। बच्चों पर सबसे कम बोझ लादने वाली मदरसा शिक्षा पद्धति, विशेष रूप से इब्तिदाई तालीम भी इसके साये में आने वाले सभी बच्चों को आगे तक तालीम जारी रखने का आकर्षण नहीं दे पाती। नतीजतन बहुत से बच्चे इसे बीच में ही छोड़ देते हैं।

1857 के विद्रोह की विफलता और मुसलमानों के भयानक दमन की पृष्ठभूमि में मदरसा षिक्षा का कुछ खास लक्ष्यों के लिए प्रतिबद्ध हो जाने के कारण उसकी सीमाएं सिकुड़ीं तथा उसके स्वरूप की व्यापकता में संकुचन आया। समकालीनता से उसकी दूरी बढ़ी। निष्चय ही धार्मिक लक्ष्यों को प्रमुखता देने वालों के लिए इसका विषेष महत्व था। मदरसों ने इस्लाम तथा धार्मिक षिक्षा के प्रसार में मूल्यवान योगदान दिया, यह सच है। लेकिन हम औरंगज़ेब की अपने उस्तादों को दी गयी तंबाही को कैसे भूल सकते हैं? हम 'दर्से निज़ामी' के निर्माण की ऐतिहासिकता तथा उसकी व्यापक उपयोगिता को कैसे नज़रअंदाज़ कर सकते हैं?

मदरसा षिक्षा के पक्षधरों में इस पद्धति के पाठ्यक्रम षिक्षण प्रक्रिया को लेकर व्यापक सहमति रही है। फिर भी इन्हीं के बीच से असहमति के स्वर भी उठते रहे है। बाहर की बात तो छोड़ दीजिये। लखनऊ में स्थापित दारूल उलूम नदवतुल उलेमा इसी असहमति का प्रतीक है।

मदरसा षिक्षाा के पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री में परिवर्तन एवं उसे समकालीन जरूरतों के अनुरूप बनाने के सम्बन्ध में बराबर चर्चा होती रही है। इस विषय पर लम्बी बहसें हुई हैं। दीनी तालीमी कौंसिल जैसे सांगठनिक प्रयास भी सामने आये हैं जिसके तरह मदरसा षिक्षा को सामाजिक जरूरतों के अनुरूप ढालने की कोषिषें हुई हैं। जमाअते इस्लामी के मदरसों का पाठ्यक्रम दर्से निज़ामी से भिन्न है। जबकि नदवा में प्राइमरी सतह पर हिन्दी'–अंगेजी के इलावा कुछ दूसरे विषय पढ़ाये जाते हैं।

समूची प्राइमरी एजूकेषन के समान मदरसा षिक्षा में भी केन्द्रीयता व एकरूपता का अभाव है। सम्बद्धता के आधार पर भी भिन्नता की संभावना बनती है। सम्बद्धता की भिन्नता के पीछे मसलकी इख्तिलाफ़ बड़े कारण के रूप में मौजूद हो सकता हैं। कम से कम प्राथमिक षिक्षा के स्तर पर दुनियावी या आधुनिक तालीम के संस्थानों के समान मदरसों पर भी स्थानीयता के दबाव होते हैं। जिन्हें बहरहाल स्वीकार किया जाना चाहिये। मौलाना अबुल अली नदवी का ख्याल है कि 'मदरसा वह कारख़ाना है, जहां कल्ब व निगाह ज़ेहन व दिमाग ढलते हैं। मदरसा वह मकाम है। जहां से पूरी कायनात का हिसाब होता है ओर पूरी इंसानी जिन्दगी की निगरानी की जाती है। मौलाना मरहूम मदरसों को आलमेइस्लाम का बिजलीघर मानते थे। वह इसे सबसे मुतहरिक इदारा तस्लीम करते थे।

इस रौषनी में देखें तो मदरसे के तालीमी निज़ाम में तब्दीली की गुंजाईष अपने आप निकल आती है। ज़ाहिर सी बात है हम यहां मदरसों की मख्सूस षिनाख्त यानी कि मज़हबी तालीम में तब्दीली की हिमायत नहीं कर रहे हैं। हां, मज़हबी तालीम देने के तरीके में तब्दीली के तरीके पर जरूर गौर किया जा सकता है। असल मसला तो मदरसों में आधुनिक ज्ञान के विषयों की पढ़ाई के लिए गुंजाईष निकालने की है।

प्राइमरी सतह पर यह और भी जरूरी है। हालांकि यह एक मुष्किल अमल है। इस सतह के बच्चों पर मज़हबी तालीम का ही इतना दबाव होता है कि दूसरे उलूम की तरफ ध्यान कर पाना आसान नहीं है। बहुत जगह हिफ़्ज़े कुर्आन पर जितना जोर होता है, अरबी भाषा सीखने पर नहीं। जबकि नदवा के पाठ्यक्रम के अनुरूप अरबी भाषा की तालीम का अमल प्राइमरी सतह से ही षुरू हो जाता है। इसके साथ ही अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू, कहीं–कहीं गणित की भी इब्तिदाई तालीम दी जाती है। लखनऊ में लड़कियों के एक मदरसे ''जामिया नुरूल इस्लामें निस्वां'' में कुर्आन षरीफ की तालीम के साथ अरबी अंग्रेजी, उर्दू और फारसी भाषाएं पढ़ाई जाती है। मजहब मजहबी तारीख से तअलुक रखने वाली दूसरी किताबें भी निसाब में षामिल हैं, हिन्दी का न पढ़ाया जाना जरूर तषवीष पैदा करता है। हिसाब यानी गणित की तालीम भी गर पांचवीं क्लास तक मुम्किन हो सके तो क्या खूब। हिसाब व सम्पर्क भाषा में कच्ची होने की वजह से औरतों को अकसर नुकसान उठाना पड़ता है। वह अपनी सलाहियतों का भी पूरी तरह काम में नहीं ला पातीं, बड़ी न–नुकुर के बीच जिन बच्चियों को मदरसे जाने की इजाज़त मिलती है, वो अगर वहां थोड़ी अंग्रेजी–हिन्दी सीख सकें तो इसमें बुरा क्या है। आगे के क्लासेज में क्योंकि प्रोफेषनल कोर्सेज़ रायज हो रहे हैं, इसे देखते हुए भी प्राइमरी सतह पर कुछ तब्दीलियां जरूरी लगती हैं। इससे मदरसा षिक्षा की उपयोगिता ही बढ़ेगी।

अपने निसाबे तालीम के बारे में दीनी तालीमी कौंसिल का नज़रिया है कि –

''.....चुनानचे निसाबे तालीम इसी नुक्ताए–निगाह से मुरत्तब किया गया है कि मुसलमान बच्चे इस्लाम के बुनियादी अक़ायद, अखलाक़, इबादत, मुआमलात, सीरते मुक़द्दस सहाबाएकराम, औलिया–ए–अल्लाह के हालाते ज़िन्दगी और तारीख़े इस्लाम से जरूरी हद तक वाकिफ़ होकर एक तरफ़ पुख्ता और बेहतर मुसलमान बनकर उठें और दूसरी तरफ़ वे मुरव्विजा उलूम, हिसाब, हिन्दी, जुग़राफ़िया, तमहुन और आम मालूमात से भी बेहतरीन दस्तगाह लेकर मकतब से निकले'' (पृष्ठ 3, निसाबे तालीम दीनी तालीमी कौंसिल, उ0प्र0)

नतीजतन कौंसिल ने अपने निसाब में मज़हबी तालीम के साथ ही प्राइमरी सतह पर अख़लाक़ियात के साथ ही अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू भाषाओं के इलावा गणित, विज्ञान, इतिहास, भूगोल जैसे आधुनिक ज्ञान के विषय भी षामिल किए। उसने कई विषयों के मामले में उत्तर प्रदेष की बेसिक षिक्षा परिषद की पाठ्य पुस्तकों को अपने लिए स्वीकार किया। नदवा ने भी इस परिषद की कुछ किताबों को मंजूरी दी है। नदवा और कौंसिल ने, बल्कि जमाअते इस्लामी ने भी अपने पाठ्यक्रमों के लिए ख़ासतौर पर कुछ किताबें तैयार करवाई हैं, जिनमें बच्चों की क़िस्सुलउंबिया जो मुलतः अरबी में हैं। मदरसों में आमतौर पर इसका उर्दू अनुवाद पढ़ाया जाता है। इस्लाम की तालीम, ख़िलाफ़ते राषिदा मिसाली हुक्मरां तथा उर्दू व हिन्दी भाषाओं के ज्ञान की पुस्तकें खासतौर पर क़ाबिलेजिक्र हैं। इनमें भी मौलवी मुहम्मद इस्माईल की कक्षा I से V तक पढ़ाई जाने वाली उर्दू ज़बान की पुस्तकें बेहतर पाठ्य पुस्तक का अच्छा उदाहरण हैं।

मिलेजुले बहुधर्मी समाज के लिए जिनकी विषेष उपयोगिता है। ये किताबें बताती हैं कि मदरसों में इतिहास का दर्स दिया जाात है इन्तिषार का नहीं। हां जमाअते इस्लामी के मदरसें की कुछ किताबें इस सच्चाई पर खरी नहीं उतरतीं। तालीम के बारे में जमाअते इस्लामी अपना नजरिया इन अल्फ़ाज में बयान करती हैं, जो प्राइमरी तालीम पर भी लागू होता है।

''तालीम सिर्फ़ तद्रीसे आम ही का नाम नहीं है। यह एक ऐसा अमल है, जिसके ज़रिये एक क़ौम खुद आगही हासिल करती है और यह अमल उस क़ौम को तषकील देने वाले अफ़राद के एहसास व षुऊर को निखारने का ज़रिया होता है। यह नई नस्ल की वह तालीमोतरबीयत है जो उसे ज़िन्दगी गुज़ारने के तरीकों का षुऊर देती है और उसमें ज़िन्दगी के मक़ासिद व फ़रायज़ का एहसास पैदा करती है। तालीम ही से एक क़ौम अपने सकाफ़ती व ज़ेहनी विरसे को आइन्दा नस्लों तक पहुंचाती है और उनमें ज़िन्दगी के उन मक़ासिद से लगाव पैदा करती है, जिन्हें उसने इख़्तियार किया हुआ है। तालीम एक ज़ेहनी, जिस्मानी और अख़लाक़ी तरबीयत है और उसका मकसद ऊँचे दर्जे के ऐसे तहजीब याफ़ता मर्द और औरतें पैदा करना है, जो अच्छे इंसानों की हैसियत से और किसी रियासत के ज़िम्मेदार षहरियों की हैसियत से अपने फ़रायज़ को अंजाम देने के अहल हों।''

(इस्लाम का नज़रिया ए तालीम – प्रो0 खुर्षीद अहमद)

मदरसों में अच्छा मुसलमान व अच्छा षहरी बनाने का अमल प्राइमरी सतह से ही षुरू हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है, दूसरे एजुकेषन सिस्टम्स का भी यही तरीक़ा है। मदरसे इस मानी में ज़रूर अलग हैं कि वहां का तालीमी निज़ाम एक निष्चित आचार संहिता से बंधा होता है। बच्चे इस आचार संहिता का कितना प्रतिषत आत्मसात कर पाते या करते हैं, यह बहस का विषय हो सकता है और यह भी कि मदारिस के मुअल्लिम ख़ासतौर पर इनके जिम्मेदारान वजाते खुद इस आचार संहिता का किस हद तक पालन कर पाते हैं।

अच्छा या सच्चा मुसलमान बनाने का मतलब यह क़तई नहीं है कि मदरसे से फारिग़ हर जवान मौलवी, हाफिज़, मुअज़्ज़िन, इमाम, मुक़र्रिर, ख़तीब या मुदर्रिस ही हो। वह अपनी सलाहियतों के मुताबिक़ ज़िन्दगी के किसी भी षोबे में जा सकता है। पिछले सालों में मदरसों से फ़ारिग़ बच्चों ने ज़िन्दगी के मुख्तलिफ़ षोबों में अपनी बेहतर सलाहइयतों का सबूत दिया है। लेकिन एक अच्छे षहरी, एक सामाजिक प्राणी तथा ख़ासतौर पर एक मुसलमान होने के नाते उन पर जो ज़िम्मेदारियां आयद होती हैं, और आज उन्हें जिन चुनौतियों का सामना है, उन्हें देखते हुए सिर्फ़ इस्लामी इतिहास ही नहीं राष्ट्रीय और सामाजिक विकास का इतिहास तथा प्रमुख स्थानीय भाषा की जानकारी ज़रूरी है। अंग्रेजी का ज्ञान उनमें अतिरिक्त सामर्थ्य पैदा करेगा क्योंकि आगे की समूची षिक्षा का दारोमदार प्राइमरी षिक्षा पर होता है। इसलिए इसी सतह पर इस ज्ञान की गुंजाईष के इम्कानात तलाष करने की ज़रूरत है।

.....

प्रतिभागियों की सूची

क्रम	नाम	संस्था का नाम/स्थान
1.	श्री षफीक खान	मदरसा सिराजुल उलूम, रूदाइन, रसूलाबाद, महमूदाबाद, सीतापुर
2.	श्री मो0 रईष	मदरसा मुईनुल इस्लाम सुढ़ियामऊ, बाराबंकी
3.	श्री षमषाद अहमद	मदरसा इस्लामिया उलूम–ए–हनफिया, बाराबंकी
4.	सुश्री आयषा सिद्दीकी	मदरसा अल–नूर, बाराबंकी
5.	सुश्री आशा बाजपेई	सहारा वेलफेयर फाउण्डेषन, लखनऊ
6.	श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव	सहारा वेलफेयर फाउण्डेषन, लखनऊ
7.	प्रो0 नदीम हसनैन	लखनऊ विष्वविद्यालय, लखनऊ
8.	श्री मो0 हारून कासमी	मदरसा कासिमुल उलूम, मिठवारा, बाराबंकी
9.	हाफिज एजाज रसूल	मदरसा षहाबुल उलूम, षहाबपुर, बाराबंकी
10.	श्री मो0 इस्लाम	मदरसा फुरकानिया, बिस्वां, सीतापुर
11.	श्री मो0 फारूक अली	मदरसा तालीमुल कुरान, बिस्वां, सीतापुर
12.	श्री मो0 नसीरूल हक	मदरसा अंसारूल उलूम, बाराबंकी
13.	सुश्री जीनत वाहिद	फील्ड स्टाफ, नालंदा, बाराबंकी
14.	श्री अहमद सईद	फील्ड स्टाफ, नालंदा, बहराइच
15.	श्री अषफाक अहमद	फील्ड स्टाफ, नालंदा, सीतापुर
16.	श्री के0बी0 सिंह	बी0जी0वी0एस0, लखनऊ
17.	श्री दीबा नसीम	बेटी फाउण्डेषन, लखनऊ
18.	श्री मुफ्ती जमाल अहमद	मदरसा नूरूल हुदा, महमूदाबाद, सीतापुर
19.	श्री अजीज वारिस	मदरसा मादुल्इल्मी, बिस्वां, सीतापुर
20.	डा0 मुजम्मिल हुसैन कासमी	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली
21.	डा0 अली	एल0डी0ए0 कालोनी, लखनऊ
22.	डा0 जसीम अहमद	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली
23.	डा0 नईमुल हसन	दिल्ली विष्वविद्यालय, नई दिल्ली
24.	श्री मो0 रियाज़	मदरसा रहमानिया, बेलहरा, बाराबंकी
25.	श्री राजेष कुमार	लोकमित्र, रायबरेली
26.	श्री षाहनवाज	लोकमित्र, रायबरेली
27.	सुश्री यासमीन बानो	लोकमित्र, रायबरेली
28.	श्री मो0 आसिम	नालंदा, लखनऊ

क्रम	नाम	संस्था का नाम/स्थान
29.	श्री मो0 हिदायतउल्लाह	नालंदा, लखनऊ
30.	श्री अब्दुल वहाब	फील्ड स्टाफ, नालंदा, सीतापुर
31.	श्री ज्ञानेन्द्र षंकर पाण्डेय	यूनीसेफ, लखनऊ
32.	श्री फिरोज अहमद कासमी	मदरसा अलहुदा, बहराइच
33.	सुश्री नाहिद	प्रयत्न फाउण्डेषन, लखनऊ
34.	जर्फ	प्रयत्न फाउण्डेषन, लखनऊ
35.	श्री राकेष कुमार	पहल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, गोला, खीरी
36.	सुश्री फरजाना अंजुम	मदरसा अमीनुल कुरान, दरियाबाद, बाराबंकी
37.	श्री मो0 जफर	मदरसा अमीनुल कुरान, दरियाबाद, बाराबंकी
38.	श्री रिशी	टी0एम0टी0, लखनऊ
39.	श्री इकबाल हसन	टी0एम0टी0, लखनऊ
40.	श्री मो0 आलम	मदरसा इब्ने–अब्बास, महमूदाबाद, सीतापुर
41.	प्रो0 एस0एस0ए0 जाफरी	गिरी इंस्टीट्यूट, लखनऊ
42.	श्री मो0 तारिक	मदरसा सेराजुल उलूम पैगम्बरपुर, सीतापुर
43.	श्री मो0 अफसर	मदरसा मिस्बाहुल उलूम, चांदपुर, सीतापुर
44.	श्री अब्दुल कय्यूम	मदरसा मिस्बाहुल उलूम, चांदपुर, सीतापुर
45.	श्री तापस कुमार राय चौधरी	नालंदा, लखनऊ
46.	श्री तनवीर हसन	ई0टी0वी0, लखनऊ
47.	श्री विभु	ई0टी0वी0, लखनऊ
48.	श्री मो0 नसीम	फील्ड स्टाफ, नालंदा, बाराबंकी
49.	श्री प्रभात झा	नालंदा, लखनऊ